RNI No. DLHIN/25/A2321

DD

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 16, पृष्ठ: 08

infodivyadelhi@gmail.com

मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi

तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री | सूर्योदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

जीएसटी बचत उत्सव: मोदी ने देशवासियों को लिखा खुला पत्र

22 सितंबर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होने के साथ ही पूरे देश में 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरूआत हो गई

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'जीएसटी बचत उत्सव' पर देशवासियों को खुला पत्र लिखा है। पीएम मोदी ने लोगों को लिखे पत्र में कहा, इस वर्ष त्योहारों में हमें एक और उपहार मिल रहा है। 22 सितंबर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू होने के साथ ही पूरे देश में 'जीएसटी बचत उत्सव' की शुरूआत हो गई है। इन रिफॉर्म्स से किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सभी को फायदा होगा।

इंश्योरेंस से लेकर घर के सामान तक सब सस्ता हुआ- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, नए जीएसटी रिफॉर्म्स की विशेषता यह है कि अब मुख्य रूप से सिर्फ दो ही दरें रहेंगी। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे खाना, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट और कई अन्य सामान अब जीरो टैक्स- यानी 5% की दर से ही मिलेंगे। बाकी सामानों पर टैक्स दरें भी कम हुई हैं। घर और परिवार से जुड़ी ज्यादातर चीजें और सेवाएं अब 5% टैक्स दर से ही उपलब्ध होंगी। यानी इंश्योरेंस से लेकर घर के सामान तक सब सस्ता हुआ है। आने वाले समय में और आसान होता जाएगा। नए इंश्योरेंस प्लान भी अब जीएसटी को छोड़कर ही दिए जाएंगे।

उन्होंने लिखा, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कई दुकानदार और व्यापारियों ने अपने यहां पहले और अब के बोर्ड लगाए हैं, जिसमें लोगों को दिखाया जा रहा है कि कोई सामान कितना सस्ता हो गया है। हमारी जीएसटी यात्रा 2017 में शुरू हुई थी। तब सरकार ने अनेक वस्तुओं के टैक्सों को खत्म कर कारोबारियों को बहुत राहत मिली थी।

नागरिक देवो भव हमारा मंत्र है: मोदी

अब ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हमें और आगे ले जा रहे हैं। इसमें सिस्टम को और सरल बनाया गया है। इससे हमारे दुकानदार साथियों, लघु उद्योगों की सहूलियत और बढ़ेगी। पीएम मोदी ने कहा, नागरिक देवो भव हमारा मंत्र है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रयासों से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। देश में एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ है। अब इसे और सशक्त बनाना हमारा संकल्प है। हमारे मध्यम वर्ग की मेहनत को मजबूती देने

के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आयकर में छूट दी जा चुकी है। अब जीएसटी रिफॉर्म्स से भी मध्यम वर्ग को सीधे लाभ मिल रहा है। नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लागू करने से देशवासियों को सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे।

पीएम ने स्वदेशी अपनाने की अपील की

पीएम ने लिखा, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के हमारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो नए जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उनसे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी तेज गति मिलेगी। आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब भी आप अपने देश के कारीगरों, श्रमिकों और इंडस्ट्री के बनाए सामान

को खरीदते हैं, तो आप कई परिवारों की रोजी-रोटी में मदद करते हैं और देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं। दुकानदारों और व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि वे स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें, ये स्वदेशी है।

आम्रपाली ग्रुप के फ्लैट खरीदारों का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली
आम्रपाली के कुछ फ्लैट खरीददारों का मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों ने कोर्ट से नियुक्त रिसीवर के फ्लैट आवंटन निरस्त करने को चुनौती दी है। इन फ्लैट खरीददारों ने कहा है कि रिसीवर की कार्रवाई अनुचित और मनमाना है। यह याचिका जस्टिस संजय कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष आज लिस्ट की गई, लेकिन समयाभाव की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। याचिकाकताओं ने 2017 से पहले आम्रपाली ग्रुप के विभिन्न प्रोजेक्ट में अपने फ्लैट बुक किए थे। कई फ्लैट खरीददारों ने उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही शुरू होने से पहले बिल्डर को पर्याप्त राशि का भुगतान भी किया था। इस दौरान कोर्ट की ओर से नियुक्त रिसीवर ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर आवंटियों को निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। याचिकाकताओं का कहना है कि ये नोटिस आवंटियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच सका। इनमें कई आवंटी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और कुछ भारत के बाहर भी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका आवंटन रद्द कर दिया गया। इन याचिकाकताओं ने कई बार कोर्ट रिसीवर के दफ्तर में जाकर व्यक्तिगत मुलाकातें की और अपनी समस्या बताई, लेकिन उसका कोई समुचित जवाब नहीं मिला। इसके बाद इन याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

डॉलर की तुलना में 22 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ रुपया

नई दिल्ली
कमजोर ग्लोबल संकेतों, स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली और डॉलर की मांग में तेजी आने का असर आज भारत के मुद्रा बाजार में साफ-साफ नजर आया। मुद्रा बाजार में बने नकारात्मक माहौल के कारण रुपया आज डॉलर की तुलना में कमजोर होकर बंद हुआ।

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली
देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा है। यह इसका 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पिछले महीने जुलाई में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.7 फीसदी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस्पात, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, बिजली और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि के कारण देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन अगस्त में 6.3 फीसदी बढ़ा है। पिछले महीने जुलाई में इनका उत्पादन वृद्धि दर

3.7 फीसदी थी। पिछले साल अगस्त में यह माइनस 1.5 फीसदी थी। इससे पहले जुलाई, 2024 में 6.3 फीसदी की समान वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगस्त, 2024 की तुलना में अगस्त 2025 में कोयला के उत्पादन में 11.4 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई है।

लाल आतंक की रीढ़ तोड़ी जा रही है : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सोमवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो शीर्ष नक्सली नेताओं का सफाया कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत बताते हुए कहा कि हमारे सुरक्षाबल लगातार संगठित रणनीति के तहत नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर

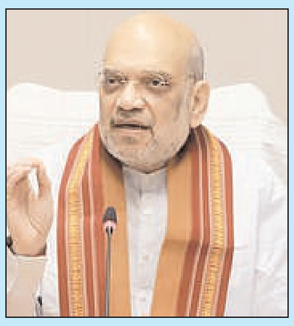

पोस्ट कर जानकारी दी कि इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की पहचान केंद्रीय समिति सदस्य कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। उन्होंने कहा, आज हमारे सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में हमारे बलों ने दो केंद्रीय समिति सदस्य नक्सल नेताओं का सफाया कर दिया। यह अभियान इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा बल देश से नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुरक्षाबलों ने अभियान के दौरान मुठभेड़ स्थल से दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए हैं।

'सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विज्ञान-समाजशास्त्र की आवश्यकता'

नई दिल्ल। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को प्रभावी बनाने कि लिए पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक पर्यावरणीय चेतना का एक हिस्सा होना चाहिए। सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विज्ञान और समाजशास्त्र की आवश्यकता है। वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के 51वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भूपेन्द्र यादव ने पिछले पांच दशकों में देश में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की सराहना की और कहा कि सीपीसीबी पर न्यायालयों और देश के नागरिकों का भरोसा है।

प्लेन क्रैश: पायलट की गलती की चर्चा अफसोसजनक: कोर्ट

अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पायलट की गलती को लेकर उठ रही चर्चाओं को अफसोसजनक बताया

नई दिल्ली
एअर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने 12 जून को दोपहर 1.38 बजे उड़ान भरी थी और 1.40 बजे हादसा हो गया। उस समय प्लेन 200 फीट की ऊंचाई पर था।

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में पायलट की गलती को लेकर उठ रही चर्चाओं को अफसोसजनक बताया है। इसके लिए कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से जवाब मांगा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बैंच ने इस मामले में स्वतंत्र जांच करवाने की संभावना पर भी ध्यान दिया है। इसको लेकर एविएशन सुरक्षा NGO सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने PIL दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जरूरी जानकारी छुपाई गई है और यह नागरिकों के जीवन, समानता और सही जानकारी पाने के अधिकार का उल्लंघन करती है। पीआईएल में कहा गया, ईंधन स्विच की खराबी और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जैसी तकनीकी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया और दुर्घटना का दोष केवल पायलट पर डाल दिया गया। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एअर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान 12 जून को टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गया

स्वतंत्र जांच की संभावनाएं तलाशें; केंद्र- और जांच एजेंसी से जवाब भी मांगा

था। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। सुमीत सभरवाल फ्लाइट के मुख्य पायलट और क्लाइव कुंदर को-पायलट थे।

कोर्ट बोला- रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित होगी

पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि दुर्घटना को हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक केवल प्रारंभिक रिपोर्ट ही जारी हुई है। उन्होंने कहा, रिपोर्ट यह नहीं बताती कि असल में क्या हुआ और भविष्य में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसका मतलब है कि आज भी इन बोइंग विमानों में यात्रा करने वाले सभी लोग खतरे में हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच की मांग सही है, लेकिन सभी निष्कर्ष सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

देश में ई-गवर्नेंस में अव्वल प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार

नई दिल्ली
देश की चार ग्राम पंचायतों को डिजिटल सेवा वितरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किए। सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किया। यह पुरस्कार पंचायती राज मंत्रालय और कार्मिक

मंत्रालय ने आपसी सहयोग से शुरू किया है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इस साल के ई-शासन पुरस्कार के लिए देश भर से आए 1.45 लाख से अधिक आवेदनों में से चार ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण को बेहतर बनाने वाली पहल श्रेणी के तहत चुना गया।

जीएसटी की दरों में कटौती कर पीएम ने बड़ी सौगात दी: डॉ. मोहन

मुख्यमंत्री ने जन व्यापारियों और ग्राहकों से किया संवाद

भोपाल
प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को जीएसटी रिफॉर्म जन जागरण अभियान के अंतर्गत राजधानी भोपाल के सोमवारा, भवानी चौक बाजार क्षेत्र में व्यापारियों एवं ग्राहकों से संपर्क कर जीएसटी की घटी दरों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही खादी के कपड़े खरीदकर स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्यापारिक, सामाजिक संगठनों, ग्राहकों और आम नागरिकों से संवाद करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली छोटी से छोटी चीज भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होना चाहिए। स्वदेशी के मूल भाव को अपनाते हुए हम देश को अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। जीएसटी की दरों में कटौती कर प्रधानमंत्री जी ने देश को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्यमियों, आम जनता के कल्याण के लिए जीएसटी की दरें घटाई गई हैं। भारत स्वदेशी के भाव को लेकर ही आजाद हुआ है। हम स्वदेशी अपनाकर ही देश को और समृद्ध बना सकते हैं। जीएसटी की दरों में कटौती करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता, व्यवसायियों, उद्यमियों को जो उपहार दिया है, उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश समृद्ध हो रहा है। वे सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं।

बीएसएफ प्रहरियों के लिए 'ई-लीव मॉड्यूल' लॉन्च, अब एक क्लिक पर होगा छुट्टी का आवेदन

नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 272447 प्रहरियों (स्वीकृत संख्या 1/1/2025 के अनुसार) के लिए 'ई-लीव मॉड्यूल' लॉन्च किया गया है। इसका फायदा यह होगा कि अब एक क्लिक के जरिए सिपाही से लेकर एडीजी तक के अधिकारी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, एक क्लिक से ही वे अपने आवेदन का स्टेट्स भी जान सकेंगे। इसके अलावा किस कार्मिक की किस मद में कितनी छुट्टियां बची हुई हैं, यह भी एक सेकेंड में पता चल जाएगा। यह पहल फोर्स में न केवल दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी, बल्कि अनावश्यक देरी को भी खत्म करेगी। मैन्युअल कागजी कार्रवाई की चुनौतियां भी कम होंगी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने प्रहरी मोबाइल एप्लिकेशन के ई-लीव मॉड्यूल का उद्घाटन किया है। खास बात है कि इस एप्लिकेशन को 'सीमा सुरक्षा बल' की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा विकसित किया गया है। यह पहल सीमा पर तैनात बीएसएफ कर्मियों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त मंत्री पहुंचीं स्टेशनरी की दुकान, लिया जीएसटी के 'क्रियान्वयन' का जायजा

नई दिल्ली
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के 'क्रियान्वयन' का राजधानी नई दिल्ली के कई इलाकों का भ्रमण करके जायजा लिया। सीतारमण ने इसी कड़ी में लक्ष्मी नगर में एक स्टेशनरी एवं किराना की दुकान पर पहुंचकर देखा कि जीएसटी बचत उत्सव के तहत लागू सुधारों का आम लोगों को फायदा मिल रह केंद्रीय वित्त मंत्री ने नवरात्रि के पहले दिन अगली पीढ़ी के जीएसटी

सुधारों के कार्यान्वयन के बाद नई दिल्ली के सुभाष चौक और लक्ष्मी नगर का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने दुकानदारों और ग्राहकों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने इस मुलाकरत के दौरान दुकानदारों और उपभोक्ताओं का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। सीतारमण ने जीएसटी सुधारों पर शुरूआती प्रतिक्रियाओं का जायजा लेने के लिए स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की।

वित्त मंत्री ने इस दौरान सभी को भारत में निर्मित 'स्वदेशी' उत्पादों को खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं के जवाब देते हुए कहा, "प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है।" इस अवसर पर सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग तथा कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा भी उपस्थित थे।

यूपी पुलिस की जांच, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में लोगों की जाति न पूछी जाएगी, न लिखी जाएगी, इसे जातिगत भेदभाव को कम करने में क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा

यूपी: सावधान, जाति का गुणगान किया तो जाओगे जेल

नई दिल्ली
'जातिवाद' को देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। कई बार जाति के कारण लोगों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है तो कई बार जातिगत दंभ में एक वर्ग को दूसरे वर्ग की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। आरोप यहां तक लगाए जाते हैं कि जातिवाद के कारण कई बार लोगों को विभिन्न संस्थाओं तक में भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है। इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के मामले में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब यूपी पुलिस की जांच, रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों में लोगों

की जाति न पूछी जाएगी, न लिखी जाएगी। इसे जातिगत भेदभाव को कम करने में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है।

नए आदेश के बाद पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी। सरकार के इस आदेश में यह साफ किया गया है कि अब सोशल मीडिया पर किसी जाति के महिमामंडन में कुछ कहना या किसी जाति को अपमानित करने वाली टिप्पणी करना गैरकानूनी होगा। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उपयुक्त धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जातिगत महिमामंडन करने पर लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी सकती है। वाहनों पर भी जातिगत महिमामंडन अपराध होगा। साथ ही, जातिगत रैलियां आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। यानी अब जातियों के आधार पर किसी मुद्दे पर रैली आयोजित करना संभव नहीं होगा।

सरकार के इस आदेश से समाज से जातिवाद खत्म हो जाएगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इससे यूपी पुलिस विभाग की कार्रवाई, सोशल मीडिया में जातिगत महिमामंडन करने या जातिगत महिमामंडन करने वाली रैलियों पर रोक लगेगी। इससे लगातार बढ़ती जा रही जातिगत वैमनस्य को कम करने में मदद मिलेगी।

क्यों आया ये आदेश

दरअसल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश एक मामले में एक आरोपी ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने उससे उसकी जाति पूछी। आरोपी ने इसे अपने साथ अनुचित व्यवहार करार दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति की जाति पूछना संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के दिए गए अधिकार के अनुकूल नहीं है। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

सरकार पीएमयूवाई के तहत नवरात्रि पर देगी 2.5 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत नारी शक्ति को बड़ा उपहार देने का ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) के 25 लाख मुफ्त कनेक्शन देने की घोषणा की है। नवरात्रि के शुभारम्भ के साथ ही मुफ्त 25 लाख नए पीएमयूवाई कनेक्शन की सौगात एक और प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिलाओं को देवी दुर्गा जी के सामान सम्मान देते हैं।

नवरात्रों पर हिमाचल के शक्तिपीठों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

शिमला
शारदीय नवरात्र की शुरूआत के साथ ही सोमवार सुबह से प्रदेश के शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां नैना देवी, मां चिंतपूर्णी, मां ज्वालाजी, मां ब्रजेश्वरी और मां चामुंडा देवी जैसे प्रमुख शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन करने पहुंचे हैं। मंदिरों को रंग-बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया है। पहले नवरात्रि पर मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। बिलासपुर स्थित मां नैना देवी मंदिर के कपाट रविवार रात दो बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जबकि ऊना में मां चिंतपूर्णी मंदिर सुबह चार बजे और कांगड़ा जिले में ज्वालाजी, ब्रजेश्वरी तथा चामुंडा देवी मंदिरों के कपाट सुबह पांच बजे खोले गए। राजधानी शिमला के प्रमुख मंदिरों तारादेवी, ढिंगू माता, कालीबाड़ी, कामना देवी और बीसीएस स्थित दुर्गा मंदिर को भी भव्य ढंग से सजाया गया है और सुबह से ही यहां भक्तों की आवाजाही जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, आईपीएस ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और रेंज स्तर के आईजीपी/डीआईजी को नवरात्रों के दौरान विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।

शादी के बंधन में बंधे हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य

चंडीगढ़
हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोमवार को चंडीगढ़ में पंजाब की डॉ. अमरीन कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारे में लावां ली। शादी हिंदू व सिख परंपरा के अनुसार हुई। सुबह करीब 11 बजे दोनों परिवार गुरुद्वारे पहुंचे। अमरीन कौर, सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और ओपिंद्र कौर की बेटी हैं। वह पंजाब यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। गुरुद्वारे में शादी की रस्में बेहद सादगी से पूरी हुईं। इसमें दोनों तरफ से सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। विक्रमादित्य के साथ उनकी मां प्रतिभा सिंह, बहन-बहनोई और कुछ दोस्त मौजूद रहे।

नॉर्थ-ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्टलक्ष्मी: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने 5,125.37 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया

नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पर 5,125.37 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनावरण किया।
पीएम मोदी ने राज्य के ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित एक समारोह में शि योमी जिले में दो प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसा ही अरुणाचल का पहला रंग केसरिया है। यह भूमि वीरता की भूमि है। पीएम मोदी ने कहा कि अरुणाचल की मेरी यात्रा विशेष बन गई है। नवरात्र के पहले दिन मुझे इतने खूबसूरत पहाड़ देखने को मिले। आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है। अरुणाचल को बिजली, स्वास्थ्य, पर्यटन और कई अन्य क्षेत्रों की परियोजनाएं दी गई हैं।

कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री ने ईटानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच से अरुणाचल को और पूरे पूर्वोत्तर को बहुत नुकसान हुआ है। पीएम ने कहा कि जिसके किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। वहीं, आगे जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में विकास पहुंचने में दशकों लग गए। अरुणाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है।

नॉर्थ-ईस्ट के राज्य हमारे लिए अष्टलक्ष्मी
पीएम ने कहा कि दशकों पहले की दिल्ली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और उसके लोगों की उपेक्षा की। कांग्रेस जैसी पार्टियों को लगता था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ सिर्फ 2 लोकसभा सीटें हैं, तो इस राज्य पर ध्यान क्यों दिया जाए? पूरा पूर्वोत्तर विकास में पिछड़ रहा था, हमारी प्रेरणा वोटों और सीटों की संख्या नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम का विचार है। हमारा एकमात्र मंत्र 'नागरिक देवो भवः है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हम आठ पूर्वोत्तर राज्यों की पूजा 'अष्टलक्ष्मी' के रूप में करते हैं।"

'त्रिपुरा में लेफ्ट का शासन प्रदेश को अंधेरे में धकेलने के लिए याद किया जाएगा'

वर्ष 2017-18 में आखिरी वाममोर्चा सरकार का बजट लगभग 15 हजार करोड़ था। परंतु आज 7 वर्षों में त्रिपुरा सरकार का बजट लगभग दोगुना हो चुका है। जनता को भ्रमित कर विकास को पीछे रखने की राजनीति करने वाले कम्युनिस्ट स्वयं ही पीछे रह गये। त्रिपुरा में लेफ्ट का शासन प्रदेश को अंधेरे व अराजकता में धकेलने के लिए याद किया जाएगा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म माता त्रिपुरसुंदरी की पुण्यभूमि में हुआ। जब भी मैं माता के दर्शन करने गया तो मन में ये प्रश्न उठता कि आखिर इतने विख्यात मंदिर का समुचित विस्तार क्यों नहीं किया गया? त्रिपुरसुंदरी माता का परिसर अन्य धार्मिक स्थलों की तरह भव्य और विशाल क्यों नहीं हो सकता।

त्रिपुरसुंदरी मंदिर परिसर के विस्तार से समृद्धता को मिलेगी नई पहचान

51 शक्तिपीठों में पूर्वोत्तर भारत का माता त्रिपुरसुंदरी मंदिर एक प्रमुख शक्तिपीठ है। माता त्रिपुरसुंदरी को दस महाविद्याओं की अग्रणी देवी भी माना जाता है। आस्था और श्रद्धा का यह पुण्यस्थल और तीर्थाटन की विशाल संभावनाओं वाला धार्मिक पर्यटन केंद्र अब नये रूप में बन कर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर प्रसाद परियोजना के अंतर्गत 2021 में मंदिर परिसर आधुनिकीकरण तथा श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए व मुख्य मंदिर और गर्भगृह को यथावत रखते हुए मंदिर को भव्यता प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। माता त्रिपुरसुंदरी के नाम पर ही इस स्थान का नाम त्रिपुरा पड़ा। इसीलिए माता त्रिपुरसुंदरी त्रिपुरा की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान भी हैं। ये मंदिर पूरे देश के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ही नहीं, बल्कि त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के जनजातीय समाज व बांग्लाभाषी लोगों की आस्था व एकता का केंद्र हैं। भारतवर्ष में विभिन्न जातीय-धार्मिक व भाषाई समूह हैं। अलग-अलग विचारधाराओं व पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। परंतु एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वो जनता की इच्छा-भावनाओं को प्राथमिकता दे। उनकी श्रद्धा-आस्था का सम्मान करें। परंतु मेरी स्मृति के अनुसार मुझे कभी याद नहीं आता कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के दौरान उनके किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी माता त्रिपुरासुंदरी के मंदिर में जाकर दर्शन किए हों? जो जनप्रतिनिधि जनता की श्रद्धा, आस्था और त्रिपुरा की पहचान के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं कर सके, उनकी सोच भी स्वभावतः जन विरोधी ही रही।

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरासुंदरी मंदिर में पूजा-अर्चना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं माता के मंदिर में पूजा करने और व उनके नवरूप का उद्घाटन करने आए। त्रिपुरासुंदरी का मंदिर एक ओर शांति, स्थिरता और जाति-जनजाति के मेल-मिलाप का संदेश देता है, तो दूसरी ओर तीर्थाटन के जरिए धार्मिक पर्यटन की संभावनाएँ आर्थिक विकास का मार्ग भी खोलती हैं, किंतु कम्युनिस्टों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। 2018

में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में विशिष्ट पर्यटन संभावनाओं के विकास का रोडमैप तैयार हुआ। माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर का विकास और सुविधा सुनिश्चित कर देश-विदेश से अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को त्रिपुरा की ओर आकर्षित करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। मंदिर आध्यात्मिक शक्ति व शांति का संदेश नहीं देता बल्कि इसमें प्रदेश की समृद्धि की भी अपार संभावना छिपी है। परंतु कम्युनिस्टों के लिए जनता की भावनाओं से अधिक उनकी विचारधारा ही महत्वपूर्ण रही।

केंद्र का राहत पैकेज पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ मजाक: राहुल गांधी

चंडीगढ़
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए दिए गए राहत पैकेज को नाकाफी करार देते हुए सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इसे पंजाब के लोगों के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है एक व्यापक राहत पैकेज तुरंत जारी करें। राहुल गांधी हाल ही में पंजाब दौरे पर आए थे। राहुल गांधी के रावी पार गांवों में नहीं जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पंजाब पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे गांवों में जाने से रोक दिया था। सोमवार को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा

कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। उन्होंने 10 मिनट का वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें लोगों से हुई उनकी बातचीत शामिल है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पंजाब को बाढ़ की वजह से लगभग 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ का प्रारंभिक राहत पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए हैं। फिर भी पंजाब के लोगों ने अद्भुत हिम्मत और जज्बा दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि वे एक बार फिर पंजाब को खड़ा करेंगे, उन्हें बस सहारे और मजबूती की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से फिर से आग्रह करता हूं कि तुरंत एक व्यापक राहत पैकेज जारी करें।

उत्तराखंड में नहीं बख्शे जाएंगे नकल माफिया: मुख्यमंत्री

देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नकल माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड का आने वाला समय स्थिरता और विकास के नाम रहेगा। मुख्यमंत्री धामी यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम काज संभाला तो उस वक्त, विभिन्न विभागों में करीब 22 हजार पद रिक्त पड़े हुए थे। अब सरकार के प्रयासों से 25

हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, इसमें एक भी परीक्षा में नकल का मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रकिया में बाधा न पहुंचे इसके लिए सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई। इससे कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा, जिस कारण वो सरकार का बदनाम करने का प्रयास करने लगे। रविवार को भी फिर ऐसा प्रयास किया गया, जबकि ये पेपर लीक जैसा मामला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नकल माफिया, कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षडयंत्र रच रहे हैं, इसका जल्द खुलासा होगा। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नकल माफिया को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा षडयंत्र पूर्व में भी हो चुका है, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता के साथ सभी परीक्षाओं को सम्पन्न कराकर नकल माफिया के इरादों पर पानी फेर दिया। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है, उत्तराखंड का आने वाला समय विकास और स्थिरता के नाम रहेगा।

धामी ने व्यापारियों से लिया जीएसटी स्लैब पर फीडबैक

देहरादून
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को प्रेमनगर में 'जीएसटी बचत उत्सव' कार्यक्रम में शामिल होते हुए व्यापारियों से मुलाकात कर संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नए जी.एस.टी स्लैब के बारे में फीडबैक लिया और व्यापारियों से आमजन को भी घटे हुए जी.एस.टी के बारे में जानकारी देने का भी आग्रह किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में जाकर दुकानदारों से संवाद किया। इसके साथ ही आम जन से मुलाकात कर उनको घटे हुए'नेक्स्ट जनरेशन जी.एस.टी' के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई आवश्यक उत्पादों और सेवाओं पर जी.एस.टी स्लैब में कमी की है। जिसका सीधा लाभ देश के आम जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देकर लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम करें। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे कुटीर उद्योग,स्थानीय कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे प्रदेश एवं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जब हम अपने स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देंगे, तभी हमारे ग्रामीण एवं शहरी उद्यमी सशक्त होंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी ने स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर समाज और प्रदेश के विकास में योगदान देना है। देश में आर्थिक सुधार और जनकल्याण एक साथ चल रहे हैं। जीसएसटी दरों में कमी से हर वर्ग को राहत मिली है और गृहिणियों से लेकर छोटे व्यापारियों तक, हर कोई इससे लाभान्वित हो रहा है।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रमों से जनता को सीधे संवाद का अवसर मिलता है और वे सरकार की नीतियों के लाभों को नजदीक से महसूस कर पाते हैं।

पंजाब में आम आदमी को मिलेगा दस लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त

चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को स्वास्थ्य कार्ड योजना के पंजीकरण का कार्य 23 सितंबर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसकी शुरूआत तरनतारन और बरनाला जिलों से होगी। प्रत्येक जिले में 128 पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे। पंजीकरण के लिए निवासियों को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो को साथ लाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि पंजीकरण की प्रक्रिया 10 से 15 दिनों के भीतर पूरी

कर ली जाएगी और इसके बाद यह योजना पूरे पंजाब में लागू होगी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके जरिए उन्हें हर साल 10 लाख रुपये तक का केशलेस इलाज मिल सकेगा। यह कार्ड प्रत्येक परिवार को एक स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। कार्ड धारक परिवार को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का केशलेस इलाज मिलेगा। सरकारी और निजी दोनों अस्पताल इस योजना में शामिल किए जाएंगे। बड़े ऑपरेशन, सर्जरी और गंभीर इलाज भी निशुल्क होंगे। अगर किसी व्यक्ति का पंजीकरण न हो सके, तो आधार या वोटर आईडी दिखाकर भी सुविधाएं प्राप्त की जा सकेंगी। बड़े ऑपरेशन, सर्जरी और गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल होगा। योजना में सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कारण से कोई व्यक्ति पंजीकरण नहीं करा पाता है, तो वह केवल आधार या वोटर आईडी दिखाकर भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा।

चार माह से वेतन नही मिलने पर भड़की आशा वर्कर्स, दी काम छोड़ने की धमकी

धर्मशाला
भारतीय मजदूर संघ से संबंधित आशा वर्कर यूनियन जिला कांगड़ा की बैठक सोमवार को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में आशा वर्कर्स की समस्याओं पर चर्चा करने उपरांत जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा गया। इसके उपरांत धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में आशा वर्कर यूनियन की जिलाध्यक्ष सरला राणा व सचिव विम्पी देवी ने कहा कि आशा वर्कर्स से सुबह से लेकर शाम तक काम लिया जाता है। रविवार तक की छुट्टी नहीं दी जाती लेकिन चार माह से वेतन नहीं दिया गया है और हवाला बजट न होने का दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य कर्मियों का वेतन भुगतान समय पर किया जा रहा है जबकि आशा वर्कर्स को कभी टुकड़ों में वेतन दिया जाता है तो इस बार चार माह से वेतन ही नहीं मिल पाया है।

हरियाणा:1032 अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों ने एक्सटेंशन लेटर की मांग की

चंडीगढ़
हरियाणा में चल रहे 1032 अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों के संचालकों ने सरकार ने एक्सटेंशन लेटर जारी करने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अस्थाई स्कूलों को एकमुश्त स्थाई मान्यता देने का वादा कर इसको घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन 11 वर्ष के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। भाजपा का वादा था कि सरकार बनने के बाद अस्थाई स्कूलों को नियमों में सरलीकरण करके एकमुश्त स्थाई मान्यता दी जाएगी, लेकिन अभी तक यह वायदा अधूरा है। उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत से स्कूलों को बने हुए 30 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया

है। ये अस्थाई स्कूल जमीन की शर्त को छोड़कर अन्य सभी नियमों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इन स्कूलों के भवनों के पास मकान बने हुए हैं। इनके पास खाली जगह नहीं है, ऐसे मे जमीन की शर्त पूरा करना इनके लिए संभव नहीं है। प्रांतीय महासचिव पवन राणा, रणधीर पूनिया, प्रदेश उप प्रधान कुलदीप यादव, प्रेस सचिव राजबीर ढाका व सलिंदर शास्त्री ने एमआईएस पोर्टल खोलने की मांग की।
संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश के हजारों प्राइवेट स्कूलों के एमआईएस पोर्टल तीन महीने से बंद पड़े हैं, जिस कारण इन स्कूलों में बच्चों के आनलाइन दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। इन स्कूलों का एमआईएस पोर्टल जल्द से जल्द खोला जाए। साथ ही एग्जिस्टिंग, एमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत स्कूलों का समाधान करने व स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए एक एक लाख रुपए जुमार्ने को भी माफ करने की भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है।

हरियाणा सरकार 23 सितंबर को मनाएगी शहीदी दिवस

चंडीगढ़
हरियाणा में सरकार 23 सितंबर को शहीदी दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन करके शहीदों का सम्मान करेगी। सरकार ने 23 सितंबर को पूरे प्रदेश में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया है। सोमवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश को लेकर एक ऑर्डर भी जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि सरकार ने फैसला किया है कि गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 23 सितंबर का दिन 'हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस' के रूप में मनाया जाए। इस दिन प्रत्येक जिले में जनसभाएं, समारोह, गोष्ठियां आयोजित करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। शहीदों के परिवारों और युद्ध में वीरता पुरस्कार पाने वालों को स्मृति चिह्न आदि भेंट कर सम्मानित किया जाए। इस समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों एवं कारगिल युद्ध के योद्धाओं को भी आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लागू किए गए नेक्स्टजेनजीएसटी सुधारों का जमीनी असर पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा: सीएम रेखा गुप्ता

सीएम ने हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी का दिया संदेश

त्रिनगर के तोताराम बाजार में जीएसटी बचत उत्सव में शामिल हुईं मुख्यमंत्री

नई दिल्ली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को उत्तरी दिल्ली स्थित त्रिनगर के बड़े बाजार तोताराम बाजार में व्यापारियों, दुकानदारों और उपभोक्ताओं संग जीएसटी बचत उत्सव में भागीदारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लागू किए गए नेक्स्टजेनजीएसटी सुधारों का जमीनी असर पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। सैंकड़ों जरूरी व रोजमर्रा की वस्तुओ के दाम कम होने से बाजारों में उत्साह का माहौल है। प्रत्येक उपभोक्ता के चेहरे पर मुस्कान है और हर दुकानदार और व्यापारी के चेहरे पर भी प्रसन्नता नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल, विधायक तिलकराम गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान तोता राम बाजार वालों ने पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रत्येक दुकान पर हर घर स्वदेशी, घर-घर स्वदेशी के पोस्टर लगाए और आम जनता से स्वदेशी उत्पादों को अपने घर तक पहुंचाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी की अपील हमारी जनता के लिए है और इस उपहार से सभी लोग प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का सीधा लाभ देश के हर नागरिक को मिल रहा है।

गृहणियां खुश हैं, व्यापारी खुश हैं, उपभोक्ता और आम नागरिक भी संतुष्ट हैं। दिवाली से पहले बाजारों में उत्साह का माहौल है और हर व्यक्ति इस पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हृदय से धन्यवाद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये सुधार गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, व्यापारी और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को नई ताकत देंगे और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएंगे। साथ ही व्यापारियों के हित में वर्षों से लंबित जीएसटी रिफंड को शीघ्र जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें तुरंत राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने इस नवरात्र को वास्तव में बचत उत्सव में बदल दिया है। यह केवल कर सुधार नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था और भी सुदृढ़ बनेगी।

उन्होंने आगे कहा कि नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की शक्ति का आशीर्वाद लेकर उन्होंने संकल्प लिया है कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए दिन-रात सेवा जारी रखी जाएगी।

स्वस्थ महिला सशक्त परिवार की धुरी है: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्वस्थ नारी सशक्त भारत अभियान के तहत अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। एम्स के धानुका प्रतीक्षालय में चल रहे स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचीं महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि स्वस्थ महिला सशक्त परिवार की धुरी है, जो स्वयं स्वस्थ रहेगी तो घर-दफ्तर के कामकाज और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने के काम आसानी से संपन्न कर सकेगी। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य शिविर में मौजूद महिला डॉक्टरों से भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आह्वान किया। साथ ही, एनीमिया और विटामिन की कमी को दूर करने और स्वयं को फिट रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एम्स दिल्ली प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा मरीजों को ओपीडी में परामर्श देकर और हजारों मरीजों को विभिन्न वार्डों में भर्ती करके इलाज प्रदान करता है।

रामलीला के लिए रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने 22 सितंबर से 03 अक्टूबर तक रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और संबंधित धार्मिक कार्यक्रमों के लिए रात 12:00 बजे तक लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग की अनुमति दी है, जो निर्धारित शर्तों और नॉइज पॉल्यूशन नियमों के अनुपालन पर आधारित है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया, जिसमें 22 सितंबर से 03 अक्टूबर (दोनों दिन समेत) तक रात 10:00 बजे से 12:00 मध्यरात्रि तक लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग के लिए उपराज्यपाल की सामान्य स्वीकृति है, यह फैसला जनहित में दिल्ली सरकार के अनुरोध और वर्षों से आयोजक समितियों की लंबी मांग के मद्देनजर सीमित, समय-बद्ध छूट देते हुए लिया गया। यह निर्णय त्योहारों के सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करते हुए जन-स्वास्थ्य और शांति की रक्षा भी करता है, जिसमें रिहायशी क्षेत्रों के लिए रात का ध्वनि मानक 45 डीबी (ए) लागू रहेगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, रामलीला समितियों की लंबी मांग को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने यह सुविधा प्रदान की है। उन्होंने आगे कहा, सभी आयोजकों को तय ध्वनि नियमों का पालन जरूरी होगा और कार्यक्रम निर्धारित समय पर समाप्त करने होंगे। दिल्ली सरकार की दुर्गा पूजा समिति के प्रमुख के रूप में, मंत्री मनजिंदर सिंह पीडब्ल्यूडी, वन व बागवानी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की।

पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वस्तुओं पर कर घटाया गया : कपिल

नई दिल्ली
जीएसटी सुधारों के लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने और स्वदेशी अपनाने और विकसित भारत निर्माण के संकल्प से जोड़ने के लिए सोमवार को भजनपुरा में धन्यवाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस धन्यवाद यात्रा में दिल्ली सरकार मंत्री कपिल मिश्रा, विधायक अजय महावर, भाजपा उत्तर-पूर्वी जिला अध्यक्ष यूके चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्षा पूनम चौहान, पार्षद प्रमोद गुप्ता, पार्षद रेखा रानी, मंडल अध्यक्ष विपिन कुमार मौजूद रहे। यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वस्तुओं पर कर घटाए गए हैं। इससे पहले हमेशा टैक्स बढ़ते ही देखे गए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सैकड़ों वस्तुओं पर टैक्स कम कर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है।

व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत जीएसटी सुधार : पंकज

नई दिल्ली
दिल्ली के स्वास्थ्य पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के तिलंग पुर कोटला विहार फेज-2 बाजार का दौरा करके कारोबारियों और स्थानीय नागरिकों को जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्लीवासियों को दिवाली के त्योहार से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। नवरात्र के शुभारंभ पर उन्होंने एक सच्चे बचत उत्सव की शुरूआत की है, जो कम टैक्स, सरल व्यापार और व्यापारियों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए बहुत बड़ी और सीधे तौर पर राहत है। मंत्री पंकज कुमार ने स्थानीय दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर विस्तार से समझाया कि नए जीएसटी स्लैब से कैसे रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटेंगी और छोटे कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ये सुधार आज से लागू हो गए हैं, जिनसे व्यापार आसान होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम आदमी सस्ती खरीदारी कर सकेंगे।

मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, दिल्ली जो मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों, नौकरीपेशा पेशेवरों, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों का शहर है। जीएसटी में हुए इन सुधारों से विशेष रूप से लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी सुधार आम जीवन को सरल बनाएंगे और लोगों की जेब में बचत का औ? अधिक पैसा छोड़कर व्यापार को बढ़ावा देंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से मजबूत होगी। तिलंग पुर कोटला विहार फेज-2 बाजार के स्थानीय दुकानदारों ने भी जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आखिर में पंकज कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में इस राहत को राजधानी दिल्ली में हर घर तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करेगी।

सफदरजंग अस्पताल में महिलाओं के लिए दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन

नई दिल्ली
स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (एसएनएसपीए) के तहत सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में एक दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 495 रोगियों की जांच की गई। इस मौके पर मरीजों से बातचीत करते हुए सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने कहा कि दंत रोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दांतों में या मसूढ़ों में कोई भी दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने दंत स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता, शीघ्र पहचान और निवारक दंत चिकित्सा देखभाल के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर्स फॉर यू (डीएफवाई) ने महिला रोगियों को निवारक मौखिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए मौखिक स्वच्छता किट वितरित की।

एएनसी जांच, टीबी और एनसीडी जांच, टीकाकरण और योग सत्र भी आयोजित किए गए।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने एसओएल केन्द्र स्वाध्याय भवन का उद्घाटन किया

नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) का नवनिर्मित पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र स्वाध्याय भवन का ताहिरपुर में सोमवार को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने उद्घाटन किया। लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत से बने इस आधुनिक भवन का निर्माण आधा एकड़ भूमि पर किया गया है, जिसमें दो आधारतल, भूतल और सात मंजिला संरचना है। भवन के कक्ष अत्याधुनिक उपकरणों और नवीन तकनीक से सुसज्जित हैं। इस अवसर पर भवन की द्वारशिला और मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने की। मुख्य अतिथि धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि मुक्त शिक्षा विद्यालय का यह नया क्षेत्रीय केंद्र केवल एक भवन नहीं बल्कि अवसर और सशक्तिकरण का द्वार है। उन्होंने कहा कि अर्जित करो और सीखो पहल में एसओएल की अहम भूमिका है, जहां युवाओं को विकसित भारत के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास दिया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा को विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुलभ बना सकती है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन को साकार करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वाध्याय भवन इस बात का प्रमाण है कि एसओएल अपने विद्यार्थियों को नियमित कॉलेजों के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पश्चिमी और दक्षिणी परिसरों को भी और अधिक विकसित करने के लिए सहयोग देने की घोषणा की। कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि अब समय है कि एसओएल में सेल्फ लर्निंग मटेरियल को और रोचक बनाया जाए, इसके लिए छोटे-छोटे वीडियो, ग्राफिक्स और एनीमेशन का उपयोग करना होगा। उन्होंने स्किल बेस्ड कोर्सेज विकसित करने की भी आवश्यकता जताई। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह केंद्र अवसरों का द्वार है, जो सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच अब दूरी की वजह से बाधित न हो। सांसद मनोज तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

जैकलीन के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी

नई दिल्ली
उच्चतम न्यायालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ड्रोन से किया कीटनाशक दवा का छिड़काव

नई दिल्ली
दिल्ली के उप महापौर जय भगवान यादव ने सोमवार को नरेला क्षेत्र के अलीपुर में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशक दवा के छिड़काव के कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से व्यापक क्षेत्र में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया जिससे डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। इस दौरान उप महापौर जय भगवान यादव ने बताया कि 10 लीटर की टैंक क्षमता वाले ड्रोन के माध्यम से सात मिनट में दो किलोमीटर के इलाके में कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकेगा। यादव ने कहा कि इस आधुनिकतम तकनीक की सहायता से मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनियों और जलजमाव वाले क्षेत्रों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा सकेगा जहां पर निगम के कर्मचारियों को पहुंचने में दिक्कत आती है।

शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के कैंप का किया शुभारंभ

नई दिल्ली
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को जनकपुरी के पोषांगीपुर क्षेत्र के सर्वोदय सह शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए आधार कार्ड बनाने के कैंप का शुभारंभ किया। दिल्ली में पहली बार इस प्रकार किसी विधानसभा में बच्चों के लिए आधार कार्ड का कैंप लगाया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने बताया, दिल्ली के हर स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल परिसर में ही आधार एनरोलमेंट करवाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में पहले कैम्प की शुरूआत इस स्कूल की गई है। इस पहल के माध्यम से सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया अब आसान और सुविधाजनक तरीके से सीधे स्कूल परिसर में ही पूरी की जाएगी। इससे अभिभावकों और बच्चों दोनों को सुविधा मिलेगी और समय की बचत भी होगी। मंत्री आशीष सूद ने कहा, यह कदम बच्चों की शिक्षा और पहचान से जुड़ी सभी योजनाओं को सुलभ बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पहचान सुरक्षित और सरल होनी चाहिए। आधार कार्ड अब विद्यालय स्तर पर ही उपलब्ध होगा, जिससे दिल्ली में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।

सनातन संस्कारम रामलीला उत्सव का किया गया आयोजन

भगवान श्रीराम के जीवन आदर्श को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री एवं रामलीला समिति के चेयरमैन रविंद्र इंद्राज ने दिल्ली वासियों को प्रथम भव्य सनातन संस्कारम रामलीला उत्सव में आमंत्रित किया है। यह आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रोहिणी सेक्टर-23 के डीडीए रामलीला ग्राउंड में होगा। उन्होंने इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए केंद्रीय मंत्रियों, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी औपचारिक निमंत्रण भेजकर सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मंत्री इंद्राज ने सोमवार को बताया कि रामलीला की थीम परम्परा से भविष्य की ओर है। जो नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने और उन्हें उनकी दिव्य विरासत का गौरव अनुभव कराने का भी एक प्रयास है। इस उत्सव का समापन ईको-फ्रेंडली दशहरा के साथ होगा, जो पर्यावरण संरक्षण और हरित दिल्ली का संदेश देगा। सेवा पखवाड़े को केंद्र में रखते हुए नशा मुक्ति और विकसित दिल्ली संकल्प जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी पूरे आयोजन में दिए जाएंगे। साथ ही वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्पादों, स्वच्छता, जल संरक्षण और हरित दिल्ली जैसे संदेशों का भी व्यापक प्रसार होगा। आयोजकों ने कहा कि 150760 फीट के विशाल मंच पर 100 से अधिक कलाकार प्रस्तुति देंगे। अत्याधुनिक लाइटिंग, एलईडी स्क्रीन और आधुनिक तकनीकी मंचन के साथ रामकथा का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। पारंपरिक संस्कृति को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का यह एक अद्वितीय प्रयास होगा। 25 सितंबर को राम बारात, महारास रात्रि, श्याम बाबा की श्रृंगार झांकी का विशेष आयोजन होगा। डांडिया नाईट में सिंगर शिबानी कश्यप भावपूर्ण प्रस्तुति देंगी। मंत्री इंद्राज ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रथम सनातन संस्कारम रामलीला का आयोजन सनातन धर्म की महान परंपराओं, भारत की प्राचीन संस्कृति और भगवान श्रीराम के जीवन आदर्श को जन-जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास होगा।

ऑपरेशन कवच 10.0 में 63 टीमें उतरीं मैदान में, 56 गिरफ्तार

नई दिल्ली
दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन कवच 10.0 चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा। जिले पुलिस उपायुक्त डॉ. हेमंत तिवारी के अनुसार पुलिस की 63 टीमों ने इलाके में पैदल गश्त, नाकाबंदी, संदिग्ध वाहनों की जांच एवं छापेमारी कर शराब माफिया, ड्रग सप्लायर, जुआरियों और अवैध हथियार रखने वालों गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 16 मुकदमे दर्जकर 16 आरोपितों को गिरफ्तार किया और 2820 क्वार्टर व 24 बीयर बरामद की। इसी क्रम में शस्त्र अधिनियम के तहत 8 मुकदमें दर्ज कर आठ को दबोचा और चाकू बरामद किए। गैम्बलिंग के मामले में 12 मुकदमे दर्ज कर 25 लोगों को पकड़ा और 24,190 की नकदी जब्त की। इसी तरह एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 केस दर्ज कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया और 21.36 ग्राम हेरोइन और 1764 ग्राम गांजा बरामद किया गया। ऑपरेश के दौरान पुलिस ने दो वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया और पांच चोरी के वाहन बरामद किए।

संपादकीय

मार्गदर्शक मंडल: भाजपा का शक्ति संतुलन का खेल

दिलीप कुमार पाठक

भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक दशक से एक सवाल बार-बार उठता रहा है- क्या 75 साल की उम्र के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए? बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, पिछले कुछ महीनों से देश में एक बहस चल रही है कि क्या मोदी इस्तीफा देकर मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? जिस तरह से उन्होंने पीएम बनने के बाद पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जैसे दिग्गजों को जबरन मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था उसी तर्ज पर क्या पीएम मोदी किसी नए व्यक्ति के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? ऐसा लगता नहीं है क्योंकि मोदी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है, खासकर जब सबकुछ उनके कन्ट्रोल में है तो भला वे क्यों छोड़ देंगे वैसे भी सत्ता का अपना एक मजा होता है पिछले महीने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक उम्र के बाद पद छोड़ देना चाहिए, और युवाओं को मौका देना चाहिए मोहन भागवत के बयान के बाद देश में एक विमर्श छिड़ गया कि मोहन भागवत पीएम मोदी को नसीहत दे रहे हैं कि अब आप 75 साल के हो गए हैं अतः अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए परंतु विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत अपने बयान से पलट गए आरएसएस एवं भाजपा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक उम्र के बाद कुर्सी या पद त्याग देना चाहिए इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि पीएम मोदी 17 सितम्बर को 75 साल के हुए हैं, वहीँ मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के हो गए हैं तो सीधी सी बात है मोहन भागवत पलट गए क्योंकि मोदी से पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ता, और मोहन भागवत भला अपना पद क्यों छोड़ना चाहेंगे?

गौरतलब है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तब पार्टी के कई बड़े नेता इस फैसले से सहज नहीं थे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता मोदी के ख?लाफ थे मोदी को पता था कि अगर इन्हें सरकार में जगह दी गई तो उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी तभी एक तर्क गढ़ा गया कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से हट जाएँगे.ह्वभाजपा की ओर से इस नियम का कभी भी औपचारिक रूप से एलान नहीं किया गया यह पार्टी संविधान में भी दर्ज नहीं है, उस वक़्त भाजपा के नेता और प्रवक्ता ऑफ द रिकॉर्ड यह बातें पत्रकारों को बताते थे, इसका एक नैरेटिव बनाया गया था, औपचारिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया इसके बाद आडवाणी, जोशी एवं दूसरे वरिष्ठ नेताओं को 2014 में एक मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बनाया गया जानकारी के मुताबि?क इसकी आज तक एक भी बैठक नहीं हुई इस नियम को औपचारिक रूप से सबसे पहले आनंदीबेन पटेल ने स्वीकार किया था आनंदीबेन ने साल 2016 में गुजरात की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा द?िया था तब उन्होंने कहा था, ह्लमैं भी नवंबर में 75 साल की होने जा रही हूँ, मैं हमेशा से ही बीजेपी की विचारधारा, सिद्धांत और अनुशासन से प्रेरित हूँ, इसका आज तक पालन करती आई हूँ, पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 से ऊपर उम्र के नेता और कार्यकर्ता स्वेच्छा से अपना पद छोड़ रहे हैं, जिससे युवाओं को मौका मिले, यह एक बहुत अच्छी परंपरा है, मेरे भी नवंबर महीने में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं बीजेपी का 75 साल वाला नियम असल में एक सॉफ्ट गाइडलाइन था न कि सख़्त प्रावधान मोदी ने इसका इस्तेमाल वरिष्ठ नेताओं को सम्मानजनक तरीके से साइडलाइन करने के लिए किया नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्र केन्?द्रीय कैबिनेट का ह?िस्?सा थे, इसके बाद वे गवर्नर बने तब ऐसी चर्चा थी क?ि उम्र की वजह से ऐसा हुआ है बीएस येदियुरप्पा ने भी जब कनार्टक का मुख्यमंत्री पद छोड़ा था तब उनकी उम्र 78 साल थी, वहाँ भी कारण उम्र बताया गया

मोहन भागवत एवं पीएम मोदी ने 75 साल की उम्र में नेताओ का मार्गदर्शक मंडल में भेजने का जो नियम बनाया था जाहिर होता है कि अपने सीनियर नेताओं की राजनीतिक परियां तो खत्म करना उदेश्य था साथ ही कोई ऊपर अंकुश न रह जाए और कोई प्रतिद्वंदिता न रह जाए कुलमिलाकर कहा जा सकता है कि 75 की उम्र में मार्गदर्शन मंडल महज एक राजनीतिक हथियार था जिसे बड़ी होशियारी से चलाया गया कुछ महीनों से भाजपा के प्रवक्ताओं ने एक राग अलापना शुरू कर दिया है कि पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 75 साल की उम्र में नेताओ को रिटायर हो जाना चाहिए इसलिए राजनीति में शुचिता जैसी बातें अब हवा हो गई हैं

फ्लू में क्या सच में अदरक-शहद काम आता है? एक्सपर्ट्स ने बताया असली सच्चाई

देश के कई राज्यों में इन दिनों फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. फ्लू यानी इन्फ्लूएंजा एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से सांस की नली को प्रभावित करता है. यह वायरस खासकर मौसम बदलने पर अधिक एक्टिव हो जाता है. संक्रमित व्यक्ति की छींक, खांसी या नजदीकी संपर्क से यह आसानी से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है. कई बार लोग इसे सामान्य सर्दी-जुकाम समझ लेते हैं, लेकिन फ्लू उससे कहीं गंभीर हो सकता है. भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कमजोर इम्यूनिटी और साफ-सफाई की कमी की वजह से यह तेजी से फैलता है. बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह और भी खतरनाक साबित हो सकता है.

फ्लू शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, जिससे अन्य संक्रमणों का खतरा भी बढ़ जाता है. यह फेफड़ों पर असर डालकर निमोनिया जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है. फ्लू के दौरान व्यक्ति को तेज बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, लगातार खांसी, नाक बहना और थकान जैसी समस्याएं होती हैं. कई बार फ्लू पेट को भी प्रभावित करता है जिससे उल्टी, दस्त या पेट दर्द हो सकता है. कमजोरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मरीज को सामान्य काम करने में भी दिक्कत होती है. गंभीर हालात में सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी तक हो सकती है.

क्या फ्लू में असरदार है अदरक और शहद?

अदरक और शहद दोनों ही पारंपरिक रूप से खांसी-जुकाम और सर्दी से जुड़ी परेशानियों में इस्तेमाल किए जाते हैं. अदरक में मौजूद जिंजरोल नामक तत्व में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो गले की खराश को कम करने और सांस की नली को साफ करने में मदद करते हैं. वहीं, शहद में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गले को कोटिंग देकर जलन को कम करते हैं. शहद एनर्जी भी प्रदान करता है, जिससे थकान और कमजोरी में राहत मिल सकती है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बेसिक एंड क्लिनिकल फामाकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में भी पाया गया कि बच्चों में अदरक-शहद का मिश्रण खांसी की तीव्रता और बार-बार होने की समस्या को कम करने में सहायक है. दिल्ली सरकार में आयुर्वेद विभाग में डॉ. आर पी पराशर बताते हैं कि यह फ्लू का इलाज नहीं है, बल्कि इसके लक्षणों को कम करने और मरीज को आराम देने में सहायक हो सकता है. ऐसे में डॉक्टर की दवाई के साथ इसे घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है.

हरियाणा में तबादलों का संकट - शिक्षकों की उम्मीदों पर विराम

डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इस समय गहरे असमंजस और ठहराव के दौर से गुजर रही है। अप्रैल से लेकर अब तक हजारों शिक्षक अपने तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नतीजा यह है कि महीनों बाद भी कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। सरकार और विभाग ने कई बार आश्वासन दिया कि जल्द ही तबादला ड्राइव चलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज तक न तो मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित हुआ और न ही नई तबादला नीति लागू हो सकी। ऐसे में शिक्षकों के मन में असंतोष और धैर्य की सीमाएँ दोनों टूटती नजर आ रही हैं।

हरियाणा में शिक्षकों के तबादले अप्रैल में होने थे, लेकिन अब तक शुरू नहीं हो पाए। सरकार ने पहले कहा था कि सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित किया जाएगा और फिर उसी के आधार पर तबादला ड्राइव चलाई जाएगी, मगर महीनों बीत जाने के बावजूद यह परिणाम जारी नहीं हुआ। नई तबादला नीति बनाने की बात कहकर शिक्षकों को उलझाए रखा गया है, जबकि वह नीति भी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। इस देरी से हजारों शिक्षक असमंजस और निराशा में हैं, क्योंकि कई शिक्षक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उन्हें समय पर स्थानांतरण से राहत की उम्मीद थी। लगातार वादों और अधूरी तैयारियों ने उनके धैर्य की परीक्षा ले ली है। अब जरूरी है कि सरकार तुरंत मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित करे, नई नीति स्पष्ट करे और पूरी पारदर्शिता के साथ तबादला प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।

तबादले किसी भी शिक्षक के लिए केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होते। यह उनके निजी जीवन, पारिवारिक परिस्थितियों और पेशेवर संतुष्टि से गहराई से जुड़े होते हैं। वर्षों से एक ही स्थान पर काम कर रहे शिक्षकों को बदलाव की उम्मीद रहती है, वहीं दूरदराज क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को अपने परिवार और बच्चों से जुड़ने की चाह होती है। जब यह उम्मीदें लगातार अधूरी रह जाती हैं, तो उसका असर उनके मनोबल और कार्यक्षमता दोनों पर पड़ता है।

अप्रैल में सरकार ने दावा किया था कि सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके आधार पर तबादलों की प्रक्रिया को दिशा दी जाएगी। लेकिन यह परिणाम महीनों से लटका हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने नई तबादला नीति बनाने की घोषणा की, ताकि प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। यह घोषणा सुनने में आकर्षक जरूर थी, लेकिन जब नीति महीनों तक अधर में ही पड़ी रहे और शिक्षकों को उसका कोई स्पष्ट स्वरूप न दिखे, तो यह केवल समय खींचने का बहाना प्रतीत होता है।

इस पूरी देरी का सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जहाँ कुछ स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक मौजूद हैं, वहीं कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में वर्षों से पद खाली पड़े हैं। नतीजा यह है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और असमानता बढ़ रही है। मॉडल स्कूल परियोजना, जिसे शिक्षा सुधार का प्रतीक बताया गया था, उसका परिणाम ही न आना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है।

शिक्षक लगातार धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी आवाजें तेज होने लगी हैं। संघ और संगठन यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब पुरानी नीति के तहत भी प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, तो उसे बीच में क्यों रोका गया। नई नीति का हवाला देकर महीनों तक शिक्षकों को उलझाए रखना क्या केवल राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी नहीं दशार्ता? शिक्षकों का मानना है कि सरकार को यदि सचमुच पारदर्शिता चाहिए तो नीति को सार्वजनिक करना चाहिए। यदि वह तैयार नहीं है तो पुरानी नीति के तहत प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, ताकि कम से कम शिक्षकों को राहत मिल सके।

हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ शिक्षा सुधार और मॉडल स्कूलों की बातें बड़े स्तर पर की जाती रही हैं, वहाँ आज स्थिति यह है कि शिक्षकों को अपने ही भविष्य का पता नहीं। यह केवल शिक्षकों का संकट नहीं है, बल्कि छात्रों और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है। शिक्षक असंतुष्ट और परेशान रहेंगे तो वे बच्चों को पूरी निष्ठा से कैसे पढ़ा पाएंगे?

अब जबकि सितंबर भी समाप्ति की ओर है, सरकार को और देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मॉडल स्कूल का परिणाम घोषित करना जरूरी है, ताकि शिक्षकों को स्पष्टता मिल सके। इसके बाद नई नीति को सार्वजनिक करना चाहिए और यदि वह अधूरी है तो पुरानी नीति के तहत ही तबादला प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल और समयबद्ध तरीके से हो, ताकि किसी प्रकार का पक्षपात या अनुशंसा की गुंजाइश न रहे।

अंततः यह समझना होगा कि शिक्षक केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि समाज की रीढ़ हैं। उन्हें महीनों तक अनिश्चितता और प्रतीक्षा में रखना उनके साथ अन्याय है और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है। यदि सरकार सचमुच शिक्षा सुधार चाहती है, तो उसे तुरंत ठोस और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। हरियाणा के शिक्षकों का धैर्य अब अंत की ओर है, और यह समय है कि सरकार वादों और घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करे। यही एकमात्र रास्ता है जो शिक्षकों को न्याय देगा और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को संतुलन और मजबूती प्रदान करेगा।

बिहार में महागठबंधन में पढ़ सकती है दरार, कई है कारण

अशोक भाटिया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में आर जे डी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे तथा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर खुली खुली टकराहट हो गई है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 243 सीटों वाले चुनाव से ठीक पहले ये दरारें विपक्षी एकता पर सवाल खड़ी कर रही हैं, जबकि सत्ताधारी मजबूत स्थिति में है।

सबसे ताजा घटना औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में घटी, जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने महागठबंधन के कार्यकताओं की बैठक बुलाई। लेकिन आर जे डी के ब्लॉक और जिला अध्यक्षों ने साथ ही पूर्व विधायक सुरेश पासवान ने बिना वजह बताए इसका बहिष्कार कर दिया। आर जे डी नेताओं ने सोमवार को पासवान के नेतृत्व में अपनी अलग रणनीति बैठक आयोजित की, जिसमें चुनावी योजनाओं पर चर्चा हुई। पासवान, जो 2005 में आर जे डी से कुटुंबा जीत चुके हैं और तत्कालीन आर जे डी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ने कार्यकताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। यह घटना गठबंधन में बढ़ती असहमति को उजागर करती है।

वैसे तो विवाद के कई कारण है उनमें कई कारण है । पहला विवाद की जड़ सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर है। पिछले सप्ताह ऐ आइ सी सी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का सीएम फेस बिहार की जनता तय करेगी। यह बयान आर जे डी को चुभ गया, जो तेजस्वी प्रसाद यादव को गठबंधन का चेहरा बनाने पर अड़ा है। तेजस्वी, विधानसभा में विपक्ष के नेता, खुद को सीएम दावेदार बताते हुए नीतीश कुमार को दुबला-पतलासी एम और दुबारासी एम कहकर आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेसी नेताओं के सामने भी वे ऐसा कह चुके हैं।इस पर तेजस्वी ने 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में रैली में कहा, इस बार तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांटी, मुजफ्फरपुर, गायघाट–हर जगह से। सबको अपील है कि तेजस्वी को वोट दो, बिहार को आगे ले जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा, हम लौटेंगे। याद रखो, तेजस्वी सभी 243 सीटों पर मैदान में होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे गठबंधन पर दबाव बनाने और आर जे डी आधार मजबूत करने की रणनीति मानते हैं।

कांग्रेस की ओर से एन एस यू आइ प्रभारी और युवा चेहरा कन्हैया कुमार ने 9 सितंबर को पटना में मीडिया सम्मेलन में कहा, हमें 70 सीटों तक क्यों सीमित कर रहे हो? हम सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवार का फैसला पार्टी लेगी, लेकिन गठबंधन सभी सीटों पर लड़ेगा। यह बयान सीट बंटवारे पर कांग्रेस की मांग को दशार्ता है, जो 2020 की तरह 60-70 या इससे अधिक सीटें चाहती है।

विवाद की जड़ें राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से भी जुड़ी हैं, जहां आर जे डी को किनारे लगने का अहसास हुआ। कांग्रेस अब दूसरा वायदा निभाने को तैयार नहीं। सूत्रों के अनुसार, अगर सीटें कम मिलीं तो डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है, जो विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी भी दोहरा रहे हैं।

अन्य सहयोगी भी चुनौती दे रहे हैं। सी पी आइ त्र एम् एल)लिबरेशन ने 2020 में 19 सीटों पर 12 जीतीं, अब 40-45 चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आर जे डी से बातचीत में हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती, गठबंधन में शामिल होने की कोशिश कर रही है। 6 सितंबर को तेजस्वी के आवास पर हुई बैठक में आर एल जे पी औरजे एम एल को इंडिया ब्लॉक में शामिल करने पर सहमति बनी, लेकिन आर जे डी - कांग्रेस को कम सीटें मिलेंगी। 2020 में महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिलीं (आर जे डी -75, कांग्रेस-19), जबकि एन डी ए को 125। अब नए सहयोगियों से फ्रैगमेंटेशन बढ़ा है।

इससे पहले, महागठबंधन में दरार की अटकलें तब और तेज हो गईं जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक दिन पहले वामपंथी दलों (लेफ्ट) की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से कर दी थी। इसपर माकपा नेता ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।माकपा महासचिव एमए बेबी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यह बेकार बयान था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। माकपा महासचिव ने कहा कि वे अक्सर विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी उनकी तुलना भाजपा से नहीं की।उन्होने कहा कि राहुल गांधी ने आरएसएस और माकपा की तुलना की। यह बयान सही नहीं था और विपक्ष के नेता को इससे बचना चाहिए।

दरअसल, राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरएसएस और माकपा के बारे में कहा था कि दोनों ही सहानुभूति को नहीं समझते। उन्होंने केरल के पुथुपल्ली में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही।कांग्रेस के दो बार मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के दौरान राहुल भाषण दे रहे थे। इस दौरान, उन्होंने प्रदेश में सत्तारूढ़ माकपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं को जनता की कोई परवाह नहीं है।

हालांकि, राहुल के बयान पर वामपंथी नेताओं ने तुरंत निंदा नहीं की।बाद में पत्रकार से राज्यसभा सांसद बने जॉन ब्रिटास ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। ब्रिटास ने लिखा कि कांग्रेस राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से नासमझ बनाए रखने पर तुली हुई है।ब्रिटास ने उन्होंने यह भी कहा कि विडंबना यह है कि राहुल गांधी आरएसएस के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह शायद हमारे दिवंगत नेता सीताराम येचुरी से आया है।

बताया जाता है कि 2025 की शुरूआत से ही राहुल गांधी के करीब करीब हर दौरे में एक बात कॉमन नजर आती है। आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस को श्रेष्ठ बताना। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों की विचारधारा की बात करते थे। कहते थे, क्षेत्रीय दलों के पास कोई विचारधारा नहीं है। तब अखिलेश यादव निशाने पर थे, और अब तेजस्वी यादव हैं। अखिलेश यादव ने तब आंख भी दिखाई थी, शायद तेजस्वी यादव भी अब वैसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।चुनाव तो राहुल गांधी महागठबंधन के साथ ही लड़ने की करते हैं, लेकिन हर कदम पर लगता है जैसे कांग्रेस अकेले मैदान में उतरने जा रही हो। तेजस्वी यादव का बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात करना भी, राहुल गांधी के व्यवहार का जवाब ही लगती है।

गौरतलब है कि बिहार में हुए रकफ यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ ही इंडिया ब्लॉक के बैनर तले वोटर अधिकार यात्रा निकाला जाना तय हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को भी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जैसा बना देने की कोशिश की। फर्क बस यही था कि वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और बिहार महागठबंधन के और भी नेता शामिल थे। फिर भी ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को हाइजैक कर लिया हो। पूरी यात्रा में राहुल गांधी आगे आगे और तेजस्वी यादव पीछे पीछे नजर आए। कहां प्रशांत किशोर जैसे नेता कांग्रेस को लालू परिवार की पिछलग्गू पार्टी कहा करते थे, और कहां वोटर अधिकार यात्रा में लगने लगा जैसे आरजेडी ही कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई हो।

वैसे तेजस्वी यादव की तरफ से तो राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी प्रस्तावित कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह टाल गए। बल्कि, राहुल गांधी का जवाब सुनकर तो ऐसा लगा जैसे वो चाहते ही न हों कि तेजस्वी को बिहार में विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। राहुल गांधी के बयान में जो कसर बाकी रह गई थी, कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने पूरी कर दी।

दिव्यांगजन की आवाज: मुख्यधारा से जुड़ने की पुकार

डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और समावेशिता मानी जाती है। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, गरिमा और अवसर की गारंटी दी है। परन्तु जब हम समाज के उस वर्ग की ओर देखते हैं, जिन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है, तो यह गारंटी अक्सर खोखली दिखाई देती है। देश की जनगणना और हालिया सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि करोड़ों दिव्यांगजन आज भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यातायात, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में हाशिए पर हैं। संवैधानिक प्रावधान और कानून मौजूद हैं, परन्तु जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति इस सच्चाई को बयान करती है कि वे अब भी अदृश्य नागरिकों की तरह जीवन जीने को विवश हैं।

समस्या केवल भौतिक अवरोधों की नहीं है, बल्कि मानसिकता और दृष्टिकोण की भी है। समाज का बड़ा हिस्सा अब भी दिव्यांगता को दया, बोझ या त्रासदी की दृष्टि से देखता है। यह सोच दिव्यांगजन की क्षमताओं और संभावनाओं को नकार देती है। उन्हें बराबरी का अवसर देने के बजाय या तो दया का पात्र बना दिया जाता है या हंसी का विषय। भारतीय सिनेमा और टेलीविजन ने भी लंबे समय तक इन्हीं रूढ़ियों को दोहराया है। हालांकि अब धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, परन्तु यह बदलाव बहुत धीमा और सीमित है।

भारतीय न्यायपालिका ने कई बार दिव्यांगजन की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या हास्य के नाम पर किसी भी समुदाय की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता। हाल ही में दिए गए फैसलों में मीडिया और मनोरंजन उद्योग को चेताया गया कि वे दिव्यांगजन को मजाक या दया का पात्र न बनाएं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करें। इसके बावजूद समाज में गहरे जमे पूर्वाग्रह अब भी मौजूद हैं।

वास्तविक चुनौती केवल कानूनी संरक्षण से पूरी नहीं होती। समस्या यह है कि कानून और नीतियाँ लागू करने वाली संस्थाओं में पर्याप्त संवेदनशीलता और दृढ़ता का अभाव है। उदाहरण के लिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ने शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में उनके लिए आरक्षण और सुविधाओं की गारंटी दी। परन्तु स्कूलों और कॉलेजों की इमारतें अब भी सीढ़ियों से भरी हैं, सरकारी दफ्तरों में व्हीलचेयर के लिए जगह नहीं है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अब भी दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित लोगों के लिए आवश्यक विकल्प उपलब्ध नहीं कराए जाते।

दिव्यांगजन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें सक्षम नागरिक के बजाय निर्भर नागरिक मान लिया गया है। यह सोच उन्हें समाज की मुख्यधारा से दूर कर देती है। जबकि सच्चाई यह है कि अवसर और सुविधा मिलने पर दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता साबित कर सकते हैं। खेल जगत में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ इसका प्रमाण हैं। शिक्षा और साहित्य से लेकर प्रशासन और विज्ञान तक दिव्यांगजन ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। समस्या क्षमता की नहीं, बल्कि अवसर और दृष्टिकोण की है।

यदि समाज सचमुच समावेशी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी सोच बदलनी होगी। दिव्यांगजन को दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बराबरी के अधिकार और अवसर चाहिए। स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को यह सिखाना होगा कि विविधता ही समाज की ताकत है। मीडिया और सिनेमा को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे दिव्यांगता को केवल दुर्बलता के रूप में न दिखाएं, बल्कि उसे साहस, आत्मविश्वास और मानवीय गरिमा से जोड़कर पेश करें।

सार्वजनिक ढांचे को दिव्यांगजन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मेट्रो स्टेशन, रेलवे प्लेटफार्म, बस अड्डे, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पार्क और शैक्षणिक संस्थान तब तक समावेशी नहीं कहे जा सकते, जब तक वे हर व्यक्ति के लिए सुलभ न हों। तकनीकी प्रगति इस दिशा में बहुत मददगार हो सकती है। डिज़िटल ऐप्स में वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन रीडर और सांकेतिक भाषा की सुविधाएँ जोड़कर हम लाखों दिव्यांगजन को ऑनलाइन शिक्षा और रोजगार से जोड़ सकते हैं।

समानता की इस लड़ाई में सरकार और समाज दोनों की साझी भूमिका है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिव्यांगजन के लिए बनाए गए कानून केवल कागजी दस्तावेज बनकर न रह जाएँ।

जेन जी प्रदर्शन के दौरान हुए दमन की जांच के लिए आयोग गठन

एजेंसी
काठमांडू। जेन जी प्रदर्शन के क्रम में हुए दमन की जांच के लिए रिटायर्ड जज गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर खनाल ने बताया कि इस दमन में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, पुलिस प्रमुख तथा काठमांडू के प्रमुख जिलाधिकारी की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया गया है। नेपाल की केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीआईबी के प्रमुख में डॉ मनोज के.सी. की नियुक्ति की गई है। भूटानी शरणार्थी मामले में कांग्रेस एमाले तथा माओवादी के बड़े नेताओं की भूमिका की जांच की जिम्मेदारी देने की जानकारी वित्त मंत्री खनाल ने दी। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री आरजू देउवा और पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर मिले करोड़ों रुपये की जांच की जिम्मेदारी संपत्ति शुद्धिकरण विभाग को दिया गया है।

बंगलादेश में डेंगू से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौतें : डीजीएचएस

ढाका। बंगलादेश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने कहा कि देश में डेंगू से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। बंगलादेश में एक दिन में हुई मौतों का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार इस साल मरने वालों की संख्या 179 तक पहुंच गयी है। डीजीएचएस ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रविवार सुबह आठ बजे तक देश में 740 नए संक्रमण के मामले सामने आये जिससे इस वर्ष अब तक डेंगू के कुल

मामलों की संख्या बढ़कर 41,831 हो गई है। संक्रमण के ये ताजा आंकड़े देश के कुछ हिस्सों में मच्छर जनित बीमारी के तेजी से बढ़त को दिखाते हैं। गौरतलब है कि जून-सितंबर मानसून अवधि बंगलादेश में डेंगू बुखार का मौसम माना जाता है, इस कारण इसे मच्छर जनित बीमारियों के लिए उच्च जोखिम वाला देश माना जाता है।

एजियन सागर में 5.2 तीव्रता का भूकंप

बीजिंग। एजियन सागर में अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 0120 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। यह जानकारी जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर

जियोसाइंसेज ने दी। शुरुआत में भूकंप का केंद्र 10.0 किमी की गहराई में 40.38 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 24.14 डिग्री पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया।

क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन हमलों में तीन लोगों की मौत, 16 घायल

मास्को। क्रीमिया में एक यूक्रेनी ड्रोन हमले में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी यूक्रेन के क्षेत्रीय प्रमुख सर्गेई अक्स्योनोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी। श्री अक्स्योनोव ने कहा कि यह घटना फोरोस बस्ती के पास हुई जहां फोरोस सैनिटोरियम और एक स्थानीय स्कूल भवन की कई सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। श्री अक्स्योनोव के सलाहकार ओलेग क्रायुचकोव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, फ़ोरोस स्कूल पर ड्रोन हमले में असेंबली हॉल पूरी तरह नष्ट हो गया और लाइब्रेरी को भारी नुकसान पहुंचा। एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। इससे पहले, रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि किया था कि रविवार को लगभग मास्को समययानुसार 19:30 (1630 जीएमटी) बजे यूक्रेन ने उच्च विस्फोटक हथियारों से लैस ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमला किया। मंत्रालय ने कहा कि यह हमला क्रीमिया के एक रिसॉर्ट क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया जहां कोई सैन्य सुविधाएं नहीं थीं।

पुर्तगाल भी ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ़िलिस्तीन को दी मान्यता, फ्रांस भी तैयार, इजराइल का रुख और कड़ा

एजेंसी
लंदन। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा के बाद पुर्तगाल ने भी ऐसे ही कदम का ऐलान कर दिया। इन देशों ने यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय आक्रोश के बीच गाजा में अभियान जारी रखने वाले इजराइल पर दबाव बनाने के लिए की है। इजराइल ने कहा कि इससे उसकी रणनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दशकों से इजराइल के मजबूत सहयोगी रहे हैं। पोलैंड के साथ इन तीनों देशों ने द्वि-राष्ट्र समाधान की दिशा में प्रगति न होने पर गहरी निराशा भी व्यक्त की है। सीएनएन चैनल की रिपोर्ट्स के अनुसार, पुर्तगाल ने कहा कि द्वि-राष्ट्र समाधान ही न्यायसंगत और स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग है। अब फ्रांस व अन्य देशों के कदमों का इंतजार है। उम्मीद है कि फ्रांस और कई अन्य देश इस

सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐसा ही करेंगे। इससे इजराइल का अलगाव और गहरा होगा। इजराइल के प्रमुख सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनके मतभेद और बढ़ेंगे। इन कदमों पर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा, कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा, सात अक्टूबर के भयानक नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है-आप आतंक को बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा, हमारी धरती के मध्य एक आतंकवादी राज्य को थोपने की इस ताजा कोशिश का जवाब मेरे अमेरिका से लौटने के बाद दिया जाएगा। इंतजार कीजिए।

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने कहा कि इस कदम से एक भी फिलिस्तीनी को मदद नहीं मिलेगी। एक भी बंधक को छुड़ाने में मदद नहीं मिलेगी। इससे हमें इजराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच कोई समझौता करने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने एक्स पर कहा, यह उन लोगों के लिए एक दुखद दिन है जो सच्ची शांति चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के 140 से ज्यादा अन्य सदस्य पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। यह संख्या गाजा में इजराइल के बढ़ते हमले को लेकर बढ़ती चिंता के बीच बढ़ी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक्स पर कहा, उनका देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है।

सीरिया में 05 अक्टूबर को होंगे संसदीय चुनाव, असद के बाद पहली बार मतदान

एजेंसी
दमिश्क। सीरिया में इस्लामवादी नेतृत्व वाली नई सरकार के तहत पहला संसदीय चुनाव 05 अक्तूबर को होगा। सरकारी समाचार एजेंसी 'साना' ने यह जानकारी दी। यह चुनाव पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के पिछले साल दिसंबर में सत्ता से बेदखल होने के बाद हो रहा है। असद ने लगभग 14 वर्षों तक देश पर शासन किया। नई 210 सदस्यीय पीपुल्स असेंबली को आर्थिक सुधारों, विदेश नीति से जुड़े नए समझौतों और व्यापक लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि आलोचकों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में अल्पसंख्यक समुदायों की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान सभी निर्वाचन क्षेत्रों में होगा, लेकिन स्वैदा, हसाका और रक्का प्रांतों में सुरक्षा कारणों से पहले मतदान टाला गया था। इन क्षेत्रों में हाल के महीनों में अशांति और झड़पें हुई थीं। संविधान के अनुसार, संसद की एक-तिहाई सीटें राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ द्वारा नामित की जाएंगी। अल-शराआ ने मार्च में अंतरिम काल के लिए एक संवैधानिक घोषणा जारी की थी, जिसमें इस्लामी कानून को केंद्रीय भूमिका दी गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी भी शामिल है। इसके बावजूद सत्ता के केंद्रीकरण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

फिलीपींस में भष्ट्राचार को लेकर जोरदार प्रदर्शन, 95 पुलिसकर्मी घायल, 216 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

एजेंसी
मनीला। नेपाल के बाद अब फिलीपींस के हजारों युवाओं ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े घोटाले को लेकर राजधानी मनीला में रविवार को सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया

जिसमें 95 पुलिसकर्मी घायल हुये हैं। इस दौरान 216 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को विरोध प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जल्द हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ अयाला ब्रिज, मेंडिओला और क्लारो एम. रेक्टो एवेन्यू सहित प्रमुख क्षेत्रों में झड़पें हो गयीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की।

फिलीपीनी न्यूज चैनल एबीएस-सीबीएन (एएनसी) के अनुसार गृह विभाग ने सोमवार को बताया कि 21 सितंबर को मनीला में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में 95 पुलिस कर्मी घायल हो गये और 216 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने एएनसी को बताया कि गिरफ्तार

किये गये लोगों में 127 युवा और 89 नाबालिग शामिल हैं। मनीला शहर के मेयर इस्को मोरेना ने बताया कि इनमें एक 12 साल का किशोर भी है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों, बोतलों और अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पर हमला किया जिसमें 95 जवान घायल हो गये। राजधानी क्षेत्र पुलिस कार्यालय (एनसीआरपीओ) के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल एंथनी एबेरिन ने बताया कि हिरासत में लिये गए लोगों के साथ पूछताछ पर पता चला है कि कई युवा कथित तौर पर अन्य देशों की घटनाओं से प्रेरित थे और एक लोकप्रिय रैपर से भी प्रभावित थे।

दक्षिण कोरिया परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए ट्रम्प-किम समझौते को करेगा स्वीकार

एजेंसी
सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच हुए समझौते को स्वीकार करेंगे जिसके तहत उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों से छुटकारा पाने के बजाय फिलहाल उनका उत्पादन रोकने पर सहमत होगा। ली जे-म्यांग ने बीबीसी से कहा कि उत्तर कोरिया प्रति वर्ष 15-20 अतिरिक्त परमाणु हथियार बना रहा है और अंतरिम आपातकालीन उपाय के रूप में इस पर रोक लगाना एक व्यवहार्य एवं यथार्थवादी विकल्प होगा।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर कोरिया ने 2022 में खुद को परमाणु शक्ति घोषित किया था और अपने हथियार कभी न छोड़ने की कसम खाई थी। बातचीत के पिछले प्रयास विफल रहे हैं इसलिए उत्तर कोरिया ने तब से बातचीत के सभी निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया है।जून में कार्यभार संभालने वाले राष्ट्रपति ली उत्तर कोरिया के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते

हैं तथा तनाव कम करना चाहते हैं, जो उनके पूर्ववर्ती यूं सूक येओल के कार्यकाल में बढ़ गया था, जिन पर पिछले वर्ष मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के लिए महाभियोग चलाया गया था। दक्षिण कोरियाई नेता इस बात को लेकर मुखर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प किम के साथ परमाणु वार्ता फिर से शुरू करें जो 2019 में श्री ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान टूट गई थी जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया से अपनी परमाणु सुविधाएं समाप्त करने के लिए कहा था।

भारतीय राजदूत की नेपाल के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, निरंतर सहयोग की उम्मीद जताई

एजेंसी
काठमांडू। नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने रविवार को अंतरिम सरकार के ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक निर्माण मंत्री कुलमन घिसिंग से मुलाकात की। मंत्री घिसिंग ने नेपाल के विकास यात्रा में भारत के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आने वाले दिनों में निरंतर सहयोग की उम्मीद जताई। यह बैठक नेपाल के हालिया राजनीतिक परिवर्तन के बाद भारत के निरंतर राजनयिक जुड़ाव के हिस्से के रूप में हुई है। राजदूत श्रीवास्तव रविवार को सिंहदरबार पहुंचे और मंत्री घिसिंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारतीय राजदूत ने मंत्री घिसिंग को जेन जी विरोध-प्रदर्शनों के बाद गठित अंतरिम सरकार में प्रमुख पोर्टफोलियो का कार्यभार संभालने पर बधाई देने के साथ ही सफल

कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ऊर्जा, परिवहन, भौतिक बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के क्षेत्र में नेपाल का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। बैठक के बाद घिसिंग ने कहा कि भारत ने नेपाल के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम उस सहयोग को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने नेपाल के विकास यात्रा में भारत के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आने वाले दिनों में निरंतर सहयोग की उम्मीद जताई। नेपाल में जेन-जी आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तनों के बाद से भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव अंतरिम सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए निरंतर मंत्रियों के संपर्क में हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ बैठक की और नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंतरिम मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों के साथ उनकी हालिया बैठकें नेपाल के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और रणनीतिक सहयोग देने में भारत की रुचि का संकेत है।

पश्चिमी इराक में दो सुरक्षाकर्मी मारे गए

एजेंसी
बगदाद। इराक के आतंकवाद निरोधी सेवा (सीटीएस) के दो सदस्य पश्चिमी प्रांत अनबार में सुरक्षा अभियान के दौरान हुए विस्फोट में मारे गए और एक खुफिया अधिकारी घायल हो गया। यह जानकारी इराकी सेना ने दी। इराकी संयुक्त ऑपरेशन कमांड से संबद्ध मीडिया आउटलेट, सिक्योरिटी मीडिया सेल ने एक बयान में कहा कि यह घटना स्थानीय समयानुसार अपराह्न 3÷00 बजे (1200 जीएमटी) हुई, जब सीटीएस और अनबर खुफिया एवं आतंकवाद निरोधक निदेशालय का एक संयुक्त बल अनबर में इस्लामिक स्टेट आतंकवादियों के ठिकानों पर हाल ही में किए गए हवाई हमले के स्थल का निरीक्षण कर रहा था। बयान में कहा गया कि तलाशी के दौरान कई विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए जिनमें से एक में विस्फोट हो गया जिससे दो सीटीएस सदस्यों की मौत हो गई तथा अनबार खुफिया एवं आतंकवाद निरोधक निदेशालय का एक अधिकारी घायल हो गया। इराक ने 2017 में आईएस पर विजय की घोषणा की लेकिन समूह के बचे हुए लड़ाके शहरों, रेगिस्तानों और दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं।

नेपाल में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट का किया विस्तार, पांच नए मंत्रियों की नियुक्ति

एजेंसी
काठमांडू। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है। उन्होंने अपने कैजिनेट में पांच नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के लिए जिन पांच मंत्रियों का नाम भेजा गया है, उनमें अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, डा संगीता मिश्रा, मदन परियार और जगदीश खरेल का नाम शामिल है। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान में इन सभी को मंत्री पद पर नियुक्त किए जाने की जानकारी दी गई है।

राष्ट्रपति भवन के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा को उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री के रूप में नियुक्ति की गई है। जस्टिस सिन्हा सुप्रीम कोर्ट के अवकाशप्राप्त जज हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार द्वारा संसद को भंग

करने के फैसले के खिलाफ में आदेश सुनाया था और संसद पुनर्गठन हो पाया था। महावीर पुन नेपाल के जाने माने वैज्ञानिक हैं और नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जीवन स्तर सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पुन को सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेपाल में हमेशा ही नए नए आविष्कार का प्रयास करने वाले महावीर पुन को शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। डॉ संगीता मिश्रा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ मिश्रा इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय में इस समय अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी और आज ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के बावजूद ओली सरकार ने उन्हें सचिव नहीं बनाया था जिसके बाद वो लंबी छुट्टी पर चली गई थी। मदन परियार नेपाल के समता फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे हैं और कृषि क्षेत्र में काफी अनुसंधान का कार्य किया है। उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जगदीश खरेल नेपाल के जाने माने पत्रकार, न्यूज एंकर और शो होस्ट हैं। नेपाल के इमेज चैनल के न्यूज डायरेक्टर हैं जिन्हें सूचना तथा संचार मंत्रालय की जानकारी दी गई है।

जलकर खंडहर बन चुके घर को देखने पहुंची ओली की पत्नी राधिका शाक्य

एजेंसी
काठमांडू। जेन जी आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ हुए केपी शर्मा ओली की पत्नी शनिवार को काठमांडू के अपने उस घर को देखने पहुंची, जो जलकर पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। घर की हालत देखकर वह काफी भावुक हो गईं। घर की बस दीवारें बची है और बाकी पूरी तरह से सामान जलकर खाक हो चुका है। राधिका शाक्य ने कहा कि घर के जलने का उन्हें उतना दुख नहीं है, लेकिन यहां कई ऐसी सामग्रियां थी, जो इतिहास को बयान करती थीं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने घर नहीं, बल्कि इतिहास को जला दिया। राधिका ने कहा वो इस घर को संग्रहालय बना कर सरकार को सौंपने का ऐलान पहले ही कर चुकी थीं, इसीलिए घर

में कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े सामानों और साहित्य को रखा गया था। ओली की पत्नी ने कहा कि जेन जी प्रदर्शनकारियों ने कभी इतिहास पढ़ा होता, तो उनको इसका महत्व समझ में आता।

दक्षिणी लेबनान में इजराइली ड्रोन हमले में 5 की मौत, 3 बच्चे भी शामिल

एजेंसी
बेरूत। लेबनान के दक्षिणी शहर बिंत जबील में इजराइली ड्रोन हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हमले में एक मोटरसाइकिल और वाहन भी निशाना बने, जिससे दो अन्य लोग घायल हुए। लोकसभा अध्यक्ष नबिह बेरी ने बताया कि मृतकों में एक पिता और उसके तीन बच्चे थे, जबकि माता घायल हैं। परिवार के सदस्य अमेरिकी नागरिक थे। इजराइली सेना ने कहा कि हमले में एक हिज्बुल्लाह सदस्य मारा गया, लेकिन 'कुछ निर्दोष नागरिक भी हताहत हुए।' सेना ने घटना की समीक्षा की घोषणा की और निर्दोषों को होने वाले नुकसान पर खेद जताया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने हमले की निंदा करते हुए इसे नागरिकों के खिलाफ खुला अपराध और दक्षिणी गांवों में लौट रहे लोगों के लिए डराने का संदेश बताया। यह हमला उस समय हुआ है जब इजराइल ने पिछले साल नवंबर में हुए अमेरिका-समझौते के बाद से हिज्बुल्लाह की छावनियों को निशाना बनाना जारी रखा है। लेबनान पर अमेरिकी, सऊदी और हिज्बुल्लाह के घरेलू विरोधियों द्वारा समूह को हथियार छोड़ने का दबाव बढ़ा है।

फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने से भड़के इजराइली प्रधानमंत्री, नेतन्याहू ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को दिखाए तेवर

एजेंसी
यरूशलम । इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा है। उन्होंने इन तीनों देशों पर 'आतंकवाद को पुरस्कृत' करने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि इजराइल जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना कभी नहीं होने देगा। नेतन्याहू ने कहा, 'हमारी जमीन पर आतंकवादी राज्य थोपने की इस नई कोशिश का जवाब मैं अमेरिका से लौटने के बाद दूंगा।' तीनों देशों की सरकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, '7 अक्टूबर के भयावह नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले नेताओं के लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है कि आप आतंक को एक बड़े इनाम से पुरस्कृत कर रहे हैं और मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।' फिलिस्तीनी राज्य के गठन के अपने पुराने विरोध को दोहराते हुए नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से मैंने घरेलू और विदेशी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य के गठन को रोका है। हमने यह दृढ़ संकल्प से किया है। इसके अलावा हमने यहूदिया और सामरिया में यहूदी बस्तियों की संख्या दोगुनी कर दी है और हम इसी राह पर चलते रहेंगे। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने का यह कदम दो-राज्य समाधान के लिए गति को फिर से बढ़ाने के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है, हालांकि इस फैसले की इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने कड़ी आलोचना की है। इजराइली विदेश मंत्री गिडिअन सार ने भी इस

निर्णय की निंदा की और इसे एक गंभीर गलती बताया। उन्होंने कहा, 'दुनिया के अधिकांश देश पहले भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे चुके हैं। यह निर्णय पहले भी गलत था, लेकिन जिन सरकारों ने अभी इसे मान्यता देने का फैसला किया है, वे अनैतिक, घिनौना और शर्मनाक काम कर रही हैं। सार का तर्क था कि इस समय जब इजरायल हमास और उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य अभियान में लगा हुआ है, ऐसे में इस तरह की मान्यता इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद जिन सरकारों ने ऐसा फैसला लिया, यह हमास के लिए पुरस्कार जैसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है।

उन्होंने बताया कि हाल ही में अमेरिका ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि वह दोषी हमलावरों को भत्ते देकर आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। हाल ही में, अमेरिका ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) और इसके नेताओं के खिलाफ कदम उठाए, क्योंकि वे आतंकवादियों को वेतन देकर पुरस्कृत करने की नीति जारी रखे हुए हैं। सार ने कहा कि वे उन देशों की विपक्षी पार्टियों के रुख से उत्साहित हैं, जिन्होंने अपने देशों की सरकारों के इस कदम का विरोध किया और इसे गलत माना। उन्होंने कहा कि इन देशों में भी हमारे कई दोस्त हैं। सार ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की संप्रभुता को बाहरी दबाव से कमजोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना नहीं होगी, क्योंकि इजराइल की जनता इसका भारी बहुमत से विरोध करती है। यह एक अव्यवहारिक विचार है। उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य लंदन या पेरिस में नहीं, बल्कि यरुशलम में तय होगा। हम उन कदमों के खिलाफ कूटनीतिक स्तर पर मजबूती से लड़ते रहेंगे, जो इजराइल और उसके भविष्य के लिए खतरा हैं।

टिकाऊ स्टार्टअप के लिए उद्योग संपर्क, निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य : जितेंद्र सिंह

एजेंसी

जम्मू। भारत के टिकाऊ स्टार्टअप और आर्थिक वृद्धि के लिए उद्योग संपर्क और निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात कही। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने यहां 'लीड इम्पैक्ट कॉन्क्लेव' को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने और भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप आजीविका के एक आकर्षक और स्थायी स्रोत के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा, '1.70 लाख स्टार्टअप के साथ, भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इनमें से लगभग 60,000 स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो सफल कृषि उद्यमी बन गई हैं।' मंत्री ने प्रासंगिक क्षेत्रों में उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने आने वाले वर्षों में प्रासंगिक विषयों पर शोध की वकालत करते हुए कहा कि अगली क्रांति जैव-चालित होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया आने वाले समय में भारत से नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है।

केरल के मुख्यमंत्री ने न्यू जर्सी के गवर्नर मर्फी को निवेश के लिए आमंत्रित किया

कोच्चि। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने न्यू जर्सी के गवर्नर फिलिप डी मर्फी और अमेरिका के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उन्हें केरल में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। एक सरकारी बयान में कहा गया कि बैठक के दौरान विजयन ने राज्य के मजबूत बुनियादी ढांचे, उच्च साक्षरता और व्यवसायों के लिए सरल प्रक्रियाओं के साथ ही निवेशक-अनुकूल वातावरण के बारे में बताया। विजयन ने कहा कि केरल और न्यू जर्सी विकास के क्षेत्र में कई समानताएं साझा करते हैं और इस बात पर जोर दिया कि निवेश और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। बयान में आगे कहा गया, केरल में उद्योगों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। पर्यटन, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों ने राज्य को निवेशकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है। चार हवाई अड्डे, 18 बंदरगाह और सरल औद्योगिक प्रक्रियाएं केरल को आकर्षक बनाती हैं। शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में उन्नत करके केरल को ज्ञान आधारित समाज बनाना है।

फेड की ब्याज दरों में कटौती, त्योहारी मांग, वैश्विक चिंताओं के बीच सोने में तेजी बनी रहेगी

नई दिल्ली। वैश्विक मौद्रिक नीतियों में ढील, एशिया में त्योहारी मांग, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और लगातार बने भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण आगामी सप्ताह में सोने की कीमतों में तेजी बनी रह सकती है। विश्लेषकों ने यह जानकारी दी। विश्लेषकों ने कहा कि व्यापारी अमेरिका और भारत के बीच होने वाली आगामी व्यापार वार्ताओं, साथ ही वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बातचीत पर बारीकी से नजर बनाए रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा, आवास संबंधी आंकड़े, व्यक्तिगत उपभोग व्यय और उपभोक्ता धारणा जैसे महत्वपूर्ण अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़े बाजार की धारणा को प्रभावित करेंगे। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज में जिंस एवं मुद्रा शोध के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा, एशिया में त्योहारी मांग में मजबूती से सर्राफा को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जबकि ईटीएफ और केंद्रीय बैंक शुद्ध खरीदार बने रहेंगे। मौजूदा उच्च कीमतों पर सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी मिली-जुली बनी हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने का वायदा भाव पिछले सप्ताह 1,616 रुपये यानी 1.5 प्रतिशत बढ़कर 1,09,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। मेर ने कहा कि सोने की कीमतों में सप्ताह के मध्य में आई गिरावट के बाद सुधार हुआ और सप्ताह के अंत में इसमें तेजी दर्ज की गई, क्योंकि ध्यान अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर, विशेष रूप से मुद्रास्फीति और रोजगार के आंकड़ों पर केंद्रित हो गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का वायदा भाव बुधवार को 3,744 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद शनिवार को 3,705.80 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।

धामी ने जनप्रतिनिधियों से जीएसटी पर जागरूकता बढ़ाने को कहा

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों और स्वदेशी अभियान पर जनप्रतिनिधियों से जनजागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दरों का लाभ आम जनता और व्यापारिक समुदाय तक तेजी से पहुंचाने के लिए प्रदेश में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से 22 से 29 सितंबर तक अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रभारी मंत्री अपने जिलों में तथा विधायक अपनी विधानसभाओं में अभियान का नेतृत्व करेंगे। देश और राज्य की आर्थिक शक्ति को बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए धामी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि स्वयं इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और इसे जन अभियान का स्वरूप दें। मुख्यमंत्री ने नए कर ढ़ाचे को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

आठ राज्यों के मूंगफली दाना कारोबारियों व ब्रोकरों ने मूंगफली व्यापार पर किया मंथन

एजेंसी

बीकानेर। रानीबाजार औद्योगिक क्षेत्र के एक निजी होटल में इंडियन पी-नट ब्रोकर्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु और पंजाब सहित विभिन्न राज्यों से जुड़े मूंगफली दाना कारोबारियों व ब्रोकरों ने भाग लिया। बैठक में बायर्स और सेलर्स दोनों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को सामने रखा। बैठक में विनोद एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रमुख विनोद बाफना, अंकित बाफना, जिंदल इंडस्ट्रीज के प्रमुख राजेश जिंदल, बीकानेर मूंगफली दाना मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भंवरलाल गोरछिया आदि उद्यमी शामिल हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश नथवाणी ने बताया कि इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य मूंगफली दाना व्यापार में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए सामूहिक मार्ग ढूँढना

है। उन्होंने कहा कि ट्रेड में फिलहाल सबसे बड़ी समस्याएँ लेट पेमेंट और जीएसटी के अनुपालन से जुड़ी हैं, जिनका समाधान निकालना जरूरी है।उन्होंने बताया कि बीकानेर को इस बैठक के लिए चुनने के पीछे विशेष कारण हैं। बीकानेर और इसके आसपास के इलाके मूंगफली दाना उत्पादन और प्रसंस्करण के बड़े केन्द्र हैं। जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े बाजार भी बीकानेर के नजदीक हैं। राजस्थान में 500 से 600 मूंगफली दाने की फैक्ट्रियाँ कार्यरत हैं, जबकि केवल गुजरात में ही करीब 2000 फैक्ट्रियाँ सक्रिय हैं। इतने बड़े उद्योग जगत को एकजुट करना आसान नहीं है, लेकिन आईपीबीए के माध्यम से इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।नथवाणी ने कहा कि पूरे भारत के फैक्ट्री ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संगठन राज्य-स्तर पर उद्योग जगत को अधिकतम एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी माना कि छोटे-मोटे मुद्दों का समाधान करके मूंगफली व्यापार को नई दिशा दी जा सकती है। बैठक में मूंगफली निर्यात से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। नथवाणी ने बताया कि एक्सपोर्ट ट्रेड में मोइश्चर, टिक्की की समस्या और दाने में स्पॉट जैसी दिक्कतें अक्सर आती हैं। ये चुनौतियाँ भारतीय मूंगफली की क्वालिटी पर असर डालती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है।

चावल-गेहूं मजबूत, खाद्य तेलों-दालों में घट-बढ़, चीनी नरम

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव में तेजी रही। गेहूं की कीमत भी बढ़ गयी। खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया, जबकि चीनी में मंदी रही। घरेलू थोक जिंस बाजारों में सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 83 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,842.74 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। गेहूं चार रुपये महंगा होकर 2,863.02 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। वहीं, आटे की कीमत 11 रुपये घट गयी और सप्ताहांत पर यह 3,323.62 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। बीते सप्ताह सरसों तेल की औसत कीमत 41 रुपये प्रति क्विंटल गिरी।

मूंगफली तेल में 105 रुपये और पाम ऑयल में 35 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गयी। सूरजमखी तेल 41 रुपये और सोया तेल 38 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ। वनस्पति के भाव में टिकाव रहा। दाल-दलहनों में उड़द दाल की औसत कीमत में 17 रुपये की साप्ताहिक तेजी दर्ज की गयी। चना दाल की कीमत 46 रुपये और मूंग दाल की 42 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी। वहीं, तुअर दाल 12 रुपये और मसूर दाल नौ रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई।

गुड़-चीनी . मीठे के बाजार में गुड़ के औसत भाव करीब 35 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गये। वहीं चीनी में 13 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट रही।

प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप : खंडेलवाल

एजेंसी

नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र नरेंद्र मोदी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर राष्ट्र को दिए गए प्रेरक संबोधन का स्वागत किया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल व्यापारिक समुदाय को आश्वस्त किया है, बल्कि देश के 140 करोड़ भारतीयों के कर तंत्र में विश्वास को भी मजबूत किया है। सांसद खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जीएसटी मात्र कर सुधार नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी, सरल और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था बनाने का सशक्त साधन है। अगली पीढ़ी के जीएसटी का उनका दृष्टिकोण व्यापारियों, उपभोक्ताओं और हर उस नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो भारत

को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहता है। कैट महामंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अनुपालन में आसानी, कर बोझ कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोग को प्रोत्साहित करने का स्पष्ट संदेश व्यापार जगत के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। उन्होंने कहा कि कैट सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि जीएसटी में सुधारों का लाभ हर छोटे व्यापारी, हर उपभोक्ता और देश के हर कोने तक पहुंचे।

जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम : कैट

एजेंसी

नई दिल्ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होने जा रही जीएसटी की नई दरों से देश के व्यापारी वर्ग को लाभ होगा और उपभोक्ताओं को भी बड़ी बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि ये सुधार स्वतंत्र भारत के सबसे क्रांतिकारी कर सुधारों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को सशक्त करना, उपभोक्ता का विश्वास बढ़ाना और देश की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन डॉलर की दिशा में अग्रसर करना है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने एक बयान में कहा कि कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों से जीएसटी दरों में हुई इस कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया है। उन?होंने कहा कि लगभग 400 वस्तुओं को 12 एवं 18 फीसदी के टैक?स स्लैब से हटाकर 5 फीसदी के स्लैब में लाया गया है। इसके अलावा 28 फीसदी के कर स्लैब को खत्म करके अधिकांश वस्तुओं को 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 15 से 20 फीसदी तक कीमतों में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। साथ ही निश्चित तौर पर वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ेगा, जिससे व्यापार में भी बड़ी वृद्धि होगी। सांसद खंडेलवाल ने कहा कि इन सुधारों से डिजिटल भारत, पारदर्शी भारत की अवधारणा को बल मिलेगा, तकनीक-आधारित प्रणाली भ्रष्टाचार कम करेगी, पारदर्शिता बढ़ाएगी और विश्वास कायम करेगी। लघु उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और छोटे दुकानदार के सबसे बड़े लाभार्थी होने के कारण आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री मोदी का विजन अधिक मजबूत होगा। खंडेलवाल ने कहा कि ये सुधार केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक उपहार हैं, जो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के और निकट ले जाएंगे।

साप्ताहिक शेयर समीक्षा : शेयर बाजार ने पांच माह में पहली बार लगातार तीसरे सप्ताह हासिल की बढ़त

एजेंसी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में हुई बिकवाली के बावजूद साप्ताहिक आधार पर लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त का सिलसिला जारी रहा। इस तरह पिछले 5 महीने के दौरान पहली बार शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त हासिल करने में सफल हुआ। शेयर बाजार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती करने और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी की वजह से काफी सहारा मिला।

इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का कोई निगेटिव असर नहीं पड़ना भी शेयर बाजार की तेजी के लिए काफी सहायक सिद्ध हुआ। 15 से 19 सितंबर तक के कारोबार के बाद सेंसेक्स साप्ताहिक आधार पर 721.53 अंक यानी 0.88 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,626.23 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी साप्ताहिक आधार पर 213.05 अंक यानी 0.83 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,327.05

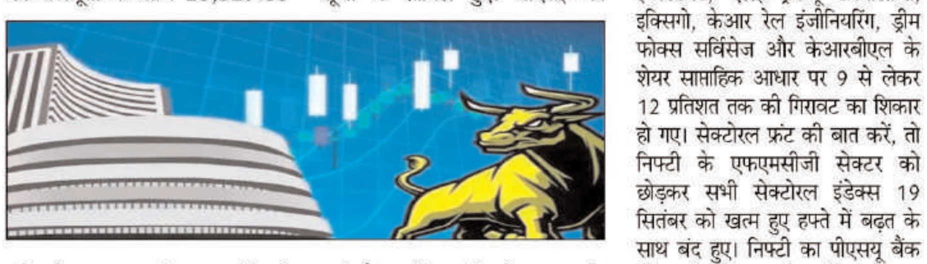

अंक के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के कारोबार में बीएसई का लार्ज कैप इंडेक्स 1.10 प्रतिशत की साप्ताहिक तेजी हासिल करके बंद हुआ। इस इंडेक्स में शामिल हुंडई मोटर इंडिया, इटरनल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, स्विगी, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, बैंक ऑफ बड़ौदा, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के शेयर टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स पिछले सप्ताह के कारोबार में दो प्रतिशत की साप्ताहिक मजबूती हासिल करने में सफल रहा। इस इंडेक्स में शामिल आईआरएम एनर्जी, बैंको प्रोडक्ट्स (इंडिया), रैमको सिस्टम, सिंधु ट्रेड लिंक्स, रेडिंग्टन, हाईटेक पाइप्स, वेलस्पन एंटरप्राइजेज, शालीमार पेंट्स रेड टेप और बजाज कंज्यूमर केयर के शेयर साप्ताहिक आधार पर 15 से 36 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुए। दूसरी ओर बामरलारी इन्वेस्टमेंट, एलई ट्रैवेन्यू टेक्नोलॉजी, इक्सिगो, केआर रेल इंजीनियरिंग, ड्रीम फोक्स सर्विसेज और केआरबीएल के शेयर साप्ताहिक आधार पर 9 से लेकर 12 प्रतिशत तक की गिरावट का शिकार हो गए। सेक्टोरल फ्रंट की बात करें, तो निफ्टी के एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स 19 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी का पीएसयू बैंक इंडेक्स पिछले सप्ताह के कारोबार के बाद साप्ताहिक आधार पर 5 प्रतिशत, निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 4 प्रतिशत, निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स 3.4 प्रतिशत, निफ्टी का एनर्जी तथा ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त के साथ बंद हुए।

शीर्ष 10 की सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1,18,328 करोड़ रुपये बढ़ा

एजेंसी

मुंबई। शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही तेजी से बीएसई की शीर्ष 10 में शामिल सात कंपनियों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 1,18,328 करोड़ रुपये बढ़ गया जबकि अन्य तीन के एमकैप में 22,095 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी। भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 35,953 करोड़ रुपये बढ़ा। इसके शेयर में 4.73 प्रतिशत की साप्ताहिक वृद्धि दर्ज की गयी थी। भारती एयरटेल का एमकैप 33,215 करोड़ रुपये, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 17,389 करोड़ रुपये और टीसीएस का 12,952 करोड़ रुपये बढ़ गया। एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 12,460 करोड़ रुपये, इंफोसिस का 6,128 करोड़ रुपये और एचडीएफसी बैंक का 230 करोड़ रुपये बढ़ा। आईसीआईसीआई बैंक का एमकैप 10,708 करोड़ रुपये घट गया। बजाज फाइनेंस के एमकैप में 6,347 करोड़ रुपये और हिंदुस्तान यूनीलिवर में 5,040 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी। बाजार

पूंजीकरण के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज 19,04,899 करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर है। एचडीएफसी बैंक 14,84,816 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और टीसीएस 11,46,879 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है।

सरकार ने कारोबारी सुगमता के लिए मंत्रालयों को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित किये

एजेंसी

नई दिल्ली। सरकार ने नियामकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड आवंटित किए गए हैं। इस कोड के तहत प्रत्येक उत्पाद को वर्गीकृत किया जाता है। इस कोड से दुनियाभर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद मिलती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि पीयूष गोयल ने 20 सितंबर को राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा तैयार नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एचएसएन) कोड के मानचित्रण पर

मार्गदर्शन पुस्तक का विमोचन किया। इसका मकसद विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और कारोबारी सुगमता के लिए डेटा आधारित नजरिये को बढ़ावा देना है। इसके महत्व पर जोर देते हुए पीयूष गोयल ने उल्लेख किया कि यह मार्गदर्शन पुस्तक घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि यह मार्गदर्शन पुस्तक 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाएगी, जिसमें शासन उद्योग की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा।

मंत्रालय के मुताबिक यह मार्गदर्शन पुस्तक भारत सरकार के 31 मंत्रालयों और विभागों को 12,167 एचएसएन कोड आवंटित करती है। इसका उद्देश्य विनिर्माण विकास, निवेश प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण को अपनाने को बढ़ावा देना है। इससे दुनियाभर में वस्तुओं के व्यवस्थित वर्गीकरण में मदद मिलती है। यह एक लचीले और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण तंत्र के निर्माण की नींव का काम करेगी।

राज्यों का वेतन-पेंशन और ब्याज खर्च 10 साल में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा, अब 15.63 लाख करोड़

एजेंसी

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों ने वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने पर होने वाला खर्च पिछले 10 साल में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा लिया है। साल 2013-14 में यह खर्च 6.26 लाख करोड़ रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 15.63 लाख करोड़ हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्यों का ज्यादातर पैसा तय खर्चों (वेतन, पेंशन और कर्ज पर ब्याज) में चला जाता है। पिछले 10 साल (2013-14 से 2022-23) में राज्यों का राजस्व खर्च उनके कुल खर्च का 80 से 87 प्रतिशत रहा। जीएसडीपी के मुकाबले यह 13-15 प्रतिशत तक बैठता है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल राजस्व खर्च 35.95 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से 15.63 लाख करोड़ रुपये वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे तय खर्चों पर गए। इसके अलावा 3.09 लाख करोड़ सब्सिडी पर और 11.26 लाख करोड़ रुपये अनुदान और सहायता पर खर्च हुए। यानी राज्यों का बजट का बड़ा हिस्सा पहले से ही बंधा हुआ है।

पेंशन से ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में खर्च

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों के खर्च में सबसे ज्यादा हिस्सा वेतन का है। इसके बाद पेंशन और फिर कर्ज पर ब्याज भुगतान आता है। लेकिन आंध्र प्रदेश, गुजरात,

हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे 9 राज्यों में पेंशन से ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में लगा।

साल 2022-23 में 17 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (यानी कमाई खर्च से ज्यादा) दिखाया। पांच राज्यों को राजस्व घाटा हुआ और छह राज्यों ने न घाटा न अधिशेष की स्थिति रखी।

एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाने से अमेरिका को भारत से ज्यादा होगा नुकसान: जीटीआरआई

एजेंसी

नई दिल्ली। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाकर प्रति कर्मचारी 100,000 अमेरिकी डॉलर करने के फैसले से भारत से ज्यादा अमेरिका को नुकसान होने की संभावना है। 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' (जीटीआरआई) ने बताया कि भारतीय आईटी कंपनियां पहले से ही अमेरिका में 50-80 प्रतिशत स्थानीय कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, जो कि कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 अमेरिकी नागरिक हैं। जीटीआरआई ने कहा, 'इसलिए यह कदम अधिक नए रोजगार नहीं पैदा करेगा। इसके बजाय, यह ऑन-साइट भारतीयों को नियुक्त करना स्थानीय लोगों की तुलना में अधिक महंगा बना देगा।' थिंक टैंक ने आगे कहा कि अमेरिका में पांच वर्षों के अनुभव वाले एक आईटी मैनेजर को 1,20,000 से 1,50,000 डॉलर तक वेतन मिलता है, जबकि एच-1बी वीजा पर आने वाले को इससे 40 प्रतिशत कम और भारत में काम करने वाले को 80 प्रतिशत कम वेतन मिलता है। जीटीआरआई के अजय श्रीवास्तव ने कहा, 'इस भारी शुल्क का सामना करते हुए, कंपनियां ऑफशोरिंग को तेज करेंगी, यानी भारत से ही रिमोट वर्क बढ़ेगा।

अगले सप्ताह प्राइमरी मार्केट में जमकर होगी हलचल, 26 नए आईपीओ की होगी लॉन्चिंग

एजेंसी

नई दिल्ली। शुरू हो रहे कारोबारी सप्ताह के दौरान प्राइमरी मार्केट में काफी हलचल रहने वाली है। इस सप्ताह दो दर्जन से ज्यादा कंपनियां अपने आईपीओ लॉन्च करने वाली हैं। इनमें 10 कंपनियों मेनबोर्ड सेगमेंट की हैं, जबकि कम से कम 16 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। इन आईपीओ के जरिए ये कंपनियां प्राइमरी मार्केट से 6,300 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने की कोशिश करेंगी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 22 सितंबर को गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 408.80 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में 24 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 306 से 322 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी स्टेपल्स और पैकेज्ड फूड सेगमेंट में काम करती है। इसी दिन अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का 687 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में भी 24 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 718 से 754 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ये कंपनी पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स का निर्माण करती है। कंपनी के शेयर 29 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। सप्ताह के अगले कारोबारी दिन 23 सितंबर को आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का 745 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में 25 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 393 से 414 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ये कंपनी रिटेल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई और संस्थागत निवेशकों को ब्रोकरेज सेवाएं देती है। कंपनी के शेयर 30 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

इसी दिन जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च का 450 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में भी 25 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 846 से 890 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ये एडटेक सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के शेयर 30 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

23 सितंबर को ही सेशासाई टेक्नोलॉजीज का 813 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में भी 25 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 402 से 423 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इसमें से 480 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 333 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर-फॉर-सेल विंडो के जरिये बेचे जाएंगे। कंपनी के शेयर 30 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे।

इस दिन का चौथा आईपीओ सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का है। 490 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में भी 25 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। आईपीओ के तहत 333 से 351 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर काम करती है। कंपनी के शेयर 30 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन 24 सितंबर को बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च होगा। इस आईपीओ में 26 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। कंपनी के आईपीओ के साइज और प्राइस बैंड का ऐलान बाद में किया जाएगा। आईपीओ के जरिये कुल 2.34 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इसी दिन ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज का 504 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इस आईपीओ में भी 26 सितंबर तक बोली लगाई जा सकेगी।

जैकलीन फर्नांडिस

ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में HC के फैसले को चुनौती

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह वही पुरानी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग मामला है. जिसमें एक्ट्रेस ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें अपने खिलाफ दर्ज स्नङ्क्रऔर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है. जिसमें 22 सितंबर यानी सोमवार को जस्टिम ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच सुनवाई करेगी. पर क्यों आखिर एक्ट्रेस को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा ? जानिए.

दरअसल यह पूरा मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस का है. जिसमें उन्होंने श्वष्ठ की ओर से दर्ज स्नङ्क्रको रद्द करने की मांग की थी. पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया. जिस पर श्वष्ठ ने कहा कि विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है. इसलिए उनकी याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है.

जैकलीन ने खटखटाया SC का दरवाजा

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. साथ ही हाईकोर्ट में एक्ट्रेस ने कहा था कि जो भी उनपर आरोप लगाए गए हैं, वो सभी झूठे हैं. उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक हिस्ट्री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. यहां तक कि जैकलीन के वकील ने भी तर्क दिया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि सुकेश से मिले तोहफे अपराध से हासिल किए पैसों से खरीदे थे. दरअसल श्वष्ठ ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन को भी सह-आरोपी बनाया है.

श्वष्ठ की तरफ से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में क्लियर कहा गया है कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर को आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की जानकारी थी. जिसके बावजूद जैकलीन ने सुकेश से कपड़े, गड़ियां, ज्वैलरी और महंगे गिफ्ट लिए थे. ऐसे में एक्ट्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में ही सबसे पहले याचिका दायर की थी. जिसमें श्वष्ठ के केस को खारिज करने के साथ ही लोअर कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.

इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की गर्लफ्रेंड थीं कटरीना कैफ, बॉक्स ऑफिस पर हुआ था ऐसा हाल

20 साल पहले साथ आए थे अभिषेक-कटरीना

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने 25 साल के एक्टिंग करियर में अब तक कई फिल्में की हैं और उनकी जोड़ी कई एक्ट्रेसेस के साथ बनी है. जहां अपनी वाइफ ऐश्वर्या राय के साथ अभिषेक ने करीब आधा दर्जन फिल्मों में काम किया तो वहीं वो बड़े पर्दे पर कटरीना कैफ के साथ भी अभिषेक नजर आ चुके हैं. 20 साल पहले आई एक पिक्चर में कटरीना ने अभिषेक की गर्लफ्रेंड का रोल किया था.

अभिषेक बच्चन ने अपना डेब्यू साल 2000 की फिल्म 'रिफ्यूजी' से किया था. वहीं कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में अपना आगाज साल 2003 की पिक्चर 'बूम' से किया था. दोनों ही कलाकारों को करियर की शुरुआत में ही साथ काम करने का मौका मिल गया था. आइए जानते हैं कि वो फिल्म कौन सी थी और उसका बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ था ?

इस फिल्म में अभिषेक की गर्लफ्रेंड थीं कटरीना

अभिषेक और कटरीना की वो 20 साल पुरानी फिल्म है 'सरकार'. इसमें दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सरकार नाम के एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया था. जूनियर बच्चन फिल्म में गैंगस्टर के बेटे शंकर के रोल में थे. वहीं कटरीना ने अभिषेक की गर्लफ्रेंड पूजा का रोल निभाया था. सरकार का हिस्सा रवि काले, तनिषा मुखर्जी, अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और के. के. मेनन जैसे कलाकार भी थे.

बॉक्स ऑफिस पर किया था कमाल

सरकार ने सिनेमाघरों में 1 जुलाई 2005 को दस्तक दी थी. इस फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया था. फिल्म को मेकर्स ने 13 करोड़ रुपये के बजट में बनाया था. वहीं पिक्चर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर करीब 25 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. जबकि वर्ल्डवाइड इसने 38 करोड़ रुपये बटोरे थे. इस हिसाब से सरकार बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी.

अभिषेक-कटरीना का वर्कफ्रंट

अभिषेक बच्चन को हाल ही में फिल्म 'कालीधर लापता' में देखा गया था. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. अब वो फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे, जिसमें लीड रोल शाहरुख खान दिखाई देंगे. कटरीना की बात करें तो एक्ट्रेस लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो पिछली बार फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. हालांकि ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी.

जिस फिल्म से भिड़ेंगे कार्तिक आर्यन, उसपर आया खतरा! दिवाली की महा'जंग' में 2 का खेल क्या है?

इस साल कई बड़ी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ. तो कुछ छोटे बजट की फिल्मों ने इम्प्रेस किया. इस साल के कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं. जिसमें कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं. कई बड़े क्लैश भी देखने को मिलेंगे. जिसमें से एक बड़ी टक्कर दिवाली पर होगी, जिसमें कार्तिक आर्यन के सामने एक बड़े यूनिवर्स की फिल्म है. पर दिवाली में 3 का खेल सबसे बड़ी परेशानी बनता दिख रहा है. उस दिन आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की Thama भी आ रही है. पर दिवाली के लिए मेकर्स ने कौन सा दिन चुना है. कैसे प्री-पोस्ट दिवाली कलेक्शन में बड़ा गैप ला सकती है.

दरअसल मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अपनी अगली फिल्मों का ऐलान कर चुका है. जिसमें से कमबैक फिल्म है Thama. यह पिक्चर दिवाली पर आएगी, जिसका टीजर आ चुका है. वहीं आयुष्मान और रश्मिका मंदाना को साथ देखने के लिए फैन्स एक्साइटेड हैं. नई रिपोर्ट से पता लगा कि मेकर्स दिवाली वाले हफ्ते में फिल्म रिलीज करने की प्लानिंग कर चुके हैं. लेकिन उसमें भी 3 अलग-अलग डेट्स पर विचार किया जा रहा है. क्या है खतरा और क्या नहीं ?

दिवाली पर २ का खेल क्या है ?

1: प्री-दिवाली (17 अक्टूबर)

यह मेकर्स के लिए प्री दिवाली ऑप्शन है. शुक्रवार को मेकर्स फिल्म को रिलीज कर सकते हैं. हालांकि, इन डेट्स पर बॉक्स ऑफिस काफी स्लो रहता है. वजह है दिवाली की तैयारी. लोग पूरी तरह से फेस्टिव सीजन की तैयारी में बिजी रहते हैं. दरअसल हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर ब्लैक एडम एंड वेनम ङ्क द लास्ट डांस ने प्री फेस्टिव पीरियड में अच्छा परफॉर्म किया था. ठीक इसी तरह मेकर्स भी चांस ले सकते है. प्री फेस्टिव पीरियड में फिल्म को रिलीज करे और छुट्टी पर कलेक्शन बढ़ सकता है.

2. दिवाली के दिन रिलीज (21 अक्टूबर)

यूं तो कई फिल्मों के मेकर्स दिवाली पर फिल्में रिलीज करते हैं, ताकी अगले ही दिन कलेक्शन बढ़े. जब लोग त्योहार से फ्री हो जाए. पर कुछ सेम दिन पर फिल्म लाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते. दरअसल दिवाली पर लोग बिजी रहते हैं, तो कलेक्शन कम होगा, इस डर से फिल्में रिलीज नहीं की जातीं. यह एक तरह की हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी भी है.

दिल वालों तैयार हो जाओ... फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए कितने एक्साइटेड शान और

सचेत-परंपरा

टीवी9 अपने करोड़ों दर्शकों के लिए इस नवरात्रि के पावन मौके पर भक्ति के साथ ही संगीत के रंग भी बिखेरने के लिए तैयार है. क्योंकि टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के तीसरे फेस्ट का शुभारंभ होने जा रहा है. एक तरफ जहां पूरा देश मां दुर्गा की आराधना में डूबा रहेगा तो वहीं इन पलों को और भी भव्य एवं दिव्य बनाने के लिए टीवी 9 भी खास तैयारियां कर रहा है. दिल्ली में पांच दिनों (28 सितंबर से 2 अक्टूबर) तक चलने वाले इस उत्सव में संगीत से जुड़ी कई मशहूर हस्तियां भी हिस्सा लेने वाली हैं.टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अब तक दो सीजन सफलतापूर्वक हो चुके हैं. वहीं अब तीसरा सीजन और भी भव्यता के साथ लौट रहा है. इस दौरान दर्शकों को कई रंगारंग कार्यक्रम और प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी. इस उत्सव में मशहूर सिंगर शान के अलावा सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर भी शिरकत करेंगे. आइए जानते हैं कि वो कहां और कब प्रस्तुति देने वाले हैं ? उन्होंने खुद वीडियो के जरिए अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है.

इस तारीख को परफॉर्म करेंगे सचेत-परंपरा

सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में परफॉर्म करने के लिए एक्साइटेड हैं. दोनों ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है. दोनों मिलकर 28 सितंबर को इस फेस्ट में हिस्सा लेंगे और शाम को परफॉर्म करेंगे. सचेत ने कहा, दिल्ली एक बढ़िया सेलिब्रेशन के लिए तैयार है. हम दोनों सचेत-परंपरा लेकर आ रहे हैं अपना म्यूजिक आपके शहर में. टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में जो हो रहा है मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में. इसके आगे परंपरा ने कहा, ये शाम होने वाली है बहुत सारे म्यूजिक, डांस और खुशियों से भरी.

शान इस दिन जमाएंगे सुरों से रंग

वहीं टीवी9 के इस मंच पर मशहूर गायक शान भी अपने सुरों का

जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं. उन्होंने इसे लेकर कहा, दिल वालों तैयार हो जाओ. इस साल का टीवी9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 होगा और भी बड़ा और भी जबरदस्त और मुझे बहुत खुशी है इस साल, इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने की. 1 अक्टूबर को मैं परफॉर्म करने वाला हूं लाइव, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में. तो आइए मिलकर मनाए त्यौहारों का रंग. म्यूजिक, डांस, मस्ती के संग. मैं आपसे वादा करता हूं कि ये रात होगी एनर्जी से भरपूर, हंसी और ढेर सारी प्यारी यादों की.

ब्रांड टॉक फैशन" के 'कल्चर ब्राइडल लुक अवॉर्ड शो' में नील भट की खास मौजूदगी, मेकअप आर्टिस्ट्स और मॉडल्स को किया सम्मानित

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के पीरागढ़ी स्थित "The Maidens Crown Banquet"" "Indian culture bridal competition and award show" का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके का नेतृत्व जाने-माने शो ऑर्गनाइजर हर्षिल रम्मन ने किया, जो इससे पहले भी कई सफल फैशन इवेंट्स का आयोजन कर चुके हैं।शो की शान बढ़ाई टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर और "बिग बॉस" व "गुम है किसी के प्यार में" जैसे सुपरहिट शोज से पहचान बना चुके सेलेब्रिटी गेस्ट नील भट्ट ने। उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान जानीमानी प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट शिल्पी भटिया और रूपा राजपूत ने लाइव मेकअप क्लास भी आयोजित की गई, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट्स को नए ट्रेंड्स और टेकनीक्स पर उपयोगी टिप्स दिए गए। शो में भाग लेने वाले सभी आर्टिस्ट्स को उनके बेहतरीन कार्य के लिए सर्टिफिकेट्स से नवाजा गया।सेलेब्रिटी गेस्ट नील भट्ट ने विनर्स को अपने हाथों से ट्रॉफी और अवॉर्ड्स देकर सम्मानित किया और सभी मॉडल्स व आर्टिस्ट्स को उनके उज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं।

ब्यूटी पार्लर में काम सीखने वाली किशोरी से कर्मचारियों ने किया दुष्कर्म,गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में बीटा-दो थाना क्षेत्र में संचालित एक ब्यूटी पार्लर के दो कर्मचारियों ने वहां काम सीख रही किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

बीटा-दो थाना प्रभारी विनोद कुमार ने सोमवार को बताया कि इलाके के एक ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही किशोरी के परिजनों ने रविवार देर रात तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि बीते दिन वह काम सीखने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी। रास्ते में उसे मुलाकात पार्लर में काम करने वाले रोहन और सैफ मिल गए। उनके बहकावे में आकर वह उनके साथ चली गई और दोनों ने एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने किसी मामला न बताने के लिए धमकी दी। घर लौटने पर बेटी ने परिवार को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने बीती रात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद : बेटे ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के बिसरख थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक बेटे ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

पुलिस उपायुक्त शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में रहने वाले प्रियांशु चौधरी ने आज सुबह अपने पिता अजय चौधरी की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस परिजनों से बातचीत कर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया युवक ने मानसिक तनाव के चलते युवक ने आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में

प्रयागराज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन केशव विद्यापीठ जयपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक होगा। जिसमें शैक्षिक संगोष्ठी भी होगी और शिक्षा को लेकर वक्ता अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के माध्यमिक संवर्ग के महामंत्री डॉ संतोष शुक्ल ने दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशक से मिलकर उक्त अधिवेशन हेतु प्रतिभागी शिक्षक पदाधिकारियों हेतु अवकाश के लिए विगत दिनों आग्रह किया था। डॉ संतोष शुक्ल ने बताया कि इस सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उत्तर प्रदेश सुरेंद्र तिवारी ने केवल प्रतिभागी शिक्षकों को विशेष अवकाश के सम्बन्ध में आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को जारी किया है।

महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण, जलेसर में जुटेंगे विशिष्ट अतिथि

दिव्य दिल्ली : वीरता, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा का लोकार्पण 26 सितंबर को एटा जिले के जलेसर में किया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश और केंद्र सरकार के दिग्गज नेता, क्षेत्रीय गणमान्य अतिथि और हजारों नागरिक उपस्थित रहेंगे। आयोजन की अध्यक्षता युवराज अम्बरीष पाल सिंह, अवागढ़ स्टेट करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष ठाकुर गजेंद्र सिंह चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों की

निगरानी की और बताया कि एटा से सैकड़ों गाड़ियों में क्षत्रिय बन्धु इस अवसर पर पहुंचेंगे। आयोजन समिति ने मंच, सजावट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। समारोह में स्थानीय नागरिकों और क्षत्रिय समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी बताते हैं कि महाराणा प्रताप का यह अनावरण केवल धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे समाज को उनके वीरता और बलिदान की याद दिलाने का प्रयास है। अनावरण कार्यक्रम में शौर्य और संस्कृति की झलक पेश करने के लिए विशेष प्रस्तुति भी दी जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बैठक में महासभा के वरिष्ठ महामंत्री सुधीर चौहान, संरक्षक उमेश चौहान, उपाध्यक्ष अनुज चौहान, सचिव भूपेंद्र चौहान, सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष उमेश पुंढीर, युवा अध्यक्ष देव सोलंकी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। 26 सितंबर का यह दिन जलेसर और पूरे एटा जिले के लिए ऐतिहासिक साबित होगा, जब हजारों लोग वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के दर्शन कर गर्व अनुभव करेंगे।

वाराणसी: चौबेपुर पुलिस ने मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर पर गोलीबारी करने वाले आरोपित को दबोचा

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में चौबेपुर पुलिस ने हाल ही में हिस्ट्रीशीटर पर हुए गोलीबारी मामले के मुख्य आरोपित को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ रविवार देर रात बभनपुरा अंडरपास के पास हुई, जब पुलिस ने अंकित सिंह को गिरफ्तार किया।

डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार और एसीपी सारनाथ विजय प्रताप ने मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इसके बाद पुलिस टीम से अफसरों ने घटना की जानकारी प्राप्त की।

डीसीपी वरूणा जोन के अनुसार 11 सितम्बर को बभनपुरा चौबेपुर में एक घटना हुई थी। जिसमें एक स्थानीय युवक गौरव सिंह को कुछ युवकों ने गोली मार दी थी। जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में कुछ युवक नामजद हुए थे। इसमें मुख्य आरोपित गांव का अंकित सिंह रहा। इसक तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई थी। इसी दौरान सूचना मिली कि अंकित सिंह गांव के आसपास आने वाला

है। पुलिस टीम ने तुरन्त रात में घेराबंदी कर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान देर रात एक युवक बाइक से आता दिखा। पुलिस टीम ने उसे रूकने का संकेत किया तो वह बाइक से उतर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो अंकित ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जबाबी कार्रवाही में उसके पैर में गोली लगी तो वह गिर पड़ा। पुलिस टीम ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर लिया। मौके से बदमाश के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अंकित के आपराधिक रिकॉर्ड की छानबीन में जुटी है।

बताते चले बभनपुरा गांव में 11 सितम्बर की देर रात विवाद में हिस्ट्रीशीटर गौरव सिंह उर्फ मोनू (39) को गांव के युवकों ने गोली मार दी थी। हिस्ट्रीशीटर के पिता की तहरीर के आधार पर चौबेपुर पुलिस ने बभनपुरा के ही निवासी पांच आरोपितों वीरेंद्र सिंह, अंकित सिंह, अभिषेक सिंह, निखिल सिंह और नीरज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में चांदपुर चौकी प्रभारी अंकुर कुशवाहा को निलम्बित किया गया था। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी पुलिस अफसरों को आरोपितों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया था।

मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार, गोली लगी

फिरोजाबाद। थाना शिकोहाबाद व एसओजी टीम ने रविवार की देर रात्रि एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

सीओ शिकोहाबाद प्रवीण तिवारी ने बताया कि थाना प्रभारी शिकोहाबाद अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी सूचना मिली कि थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत 02 शातिर लुटेरे लूट की घटना करने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने छीछामई नहर पुल पर सघन चैकिंग अभियान चलाया तभी एक मोटरसाईकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जिन्हें पुलिस टीम ने रोका तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा एक अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान सूरजीत उर्फ सीटू पुत्र दाऊ दयाल निवासी नगला कन्हई थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद के रुप में हुई है।

भारत केसरी कलुआ गुर्जर ने दी हरियाणा के पुष्पेंद्र नेवी को दी पटकनी, ढाई लाख जीते

गौतम बुद्ध नगर। स्वर्गीय प्रधान श्याम सिंह की स्मृति में आयोजित 35वें विशाल दंगल में ढाई लाख रुपये इनाम की कुश्ती भारत केसरी रेलवे कलवा गुर्जर ने जीत ली है। पहलवान कलवा गुर्जर ने हरियाणा के भारत केसरी पुष्पेंद्र नेवी को एक रोमांचक मुकाबले में हराया।

नगर के सेक्टर 74 स्थित तिवोली फॉर्म के पास खुले मैदान में आयोजित दंगल रविवार दोपहर से

शुरू हुआ और देर रात तक चला।सबसे बड़ी इनामी कुश्ती के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी यादव ने दोनों पहलवानों के हाथ मिलवाए। इस अवसर पर डीपी यादव ने कहा कि कुश्ती एक भारतीय पारंपरिक खेल है। कुश्ती लड़ने वाले लोग शरीर से मजबूत, मन से स्वस्थ्य और विचार से शुद्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि देश के नौजवान जहां एक तरफ नशा और अपराध की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, वही कुश्ती और ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक खेल युवाओं को चुश्त-दुरुस्त तंदुरुस्त और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए हुए हैं। यादव ने कहा कि नोएडा जैसे महानगर में कुश्ती के आयोजन को देखने के लिए जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, यह इस बात को सिद्ध करता है कि अभी भी लोग अपने पारंपरिक खेल और संस्कृति से जुड़े हैं। दंगल के आयोजक जितेंद्र यादव और विक्रांत यादव ने बताया कि वे अपने पिता स्वर्गीय श्याम सिंह की स्मृति में हर वर्ष विशाल दंगल करवाते हैं। इस दंगल में हजारों की संख्या में पहलवान भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी कुश्ती ढाई लाख की थी। इसके अलावा 1100 रुपए से लेकर 21, 51, एक लाख 1 हजार, एक लाख 51 हजार तक की कुश्ती हुई।

यमुना की आरती कर तट पर चला स्वच्छता अभियान, अंत्येष्टि स्थलों की हुई साफ-सफाई

औरैया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सोमवार को यमुना तट पर स्थित अंत्येष्टि स्थलों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यह कार्यक्रम जिला गंगा समिति, नगर पालिका परिषद, वन विभाग और समाजसेवी संगठन एक विचित्र पहल सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से आयोजित हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अनूप गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राम आसरे कमल, सफाई निरीक्षक आशीष पांडे, डीपीएम शिरीष मिश्रा सहित समिति के पदाधिकारी व सेवादार मौजूद रहे।

समिति अध्यक्ष राजीव पोरवाल (रानू) ने बताया कि संस्था पिछले 10 वर्षों से श्मशान घाटों पर स्वच्छता व पौधारोपण कार्यक्रम लगातार करती आ रही है। समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि हर वर्ष बाढ़ के कारण यमुना घाट का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे अंत्येष्टि करने वालों को काफी असुविधा होती है। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए संस्था निरंतर प्रयासरत है।

अभियान के उपरांत घाट परिसर में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। वैदिक मंत्रोचारण के बीच घंटा-घड़ियाल, शंखनाद और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से यमुना मैया की दिव्य आरती संपन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने विधिवत पूजा-अर्चना कर आरती उतारी। उपस्थित श्रद्धालुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर यमुना जी से सुख-समृद्धि की कामना की।

आनंद नाथ गुप्ता ने कहा कि पावन यमुना नदी में स्नान, ध्यान और पूजा करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापों का नाश होता है।

आयोजन में प्रमुख रूप से विनोद पोरवाल, हिमांशु दुबे, सुधीर कुमार, किरन शर्मा, वन विभाग की जिला परियोजना अधिकारी साक्षी शुक्ला, रूबी शर्मा, विवेक अवस्थी, पवन यादव व धर्मेंद्र सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं सेवादार मौजूद रहे।

प्रयागराज: सड़क हादसे में कानपुर के चार की मौत,तीन घायल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित सोरांव थाना क्षेत्र के विगहिया गांव के पास हाइवे रविवार रात हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि हादसे में सुरेश सैनी और सुरेश की पत्नी, सुरेश बाजपेई, राम सागर अवस्थी की मौत हुई है। हादसे में घायल तीन लोगों को उपचार के लिए स्वरुपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कानपुर के मूसानगर विलौली से पिण्ड दान करने के लिए बोलेरो से गया गए थे। वहां से पिंडदान कर सभी लोग कानपुर के लिए वापस जा रहे थे। रविवार रात सोरांव थाना क्षेत्र में बिगहिया गांव के समीप हाइवे पर गाड़ी खराब हो गई। रात होने की वजह से गाड़ी खड़ी करके कार के आगे हो गए। रात में किसी बड़े वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने तत्काल सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। तीन लोगों का उपचार जारी है। हादसे की सूचना परिवार को दे दी गई है। आगे की कार्रवाई परिवार के आने के बाद की जाएगी।

नोएडा के चार प्रमुख जगहों पर आज रात से गणेश पूजा से शुरू होगी रामलीला

गौतम बुद्ध नगर। नोएडा शहर में आज से प्रमुख रूप से चार स्थानों पर रामलीलाएं शुरू हो रही है। इसके लिए सभी रामलीला मैदानों में मंच बनकर तैयार हो चुके हैं। रामलीला के कलाकर भी नोएडा पहुंचकर अभ्यास कर रहे हैं। सोमवार शाम को गणेश वंदना के बाद रामलीलाएं शुरू होगी। नोएडा स्टेडियम की रामलीला सेक्टर-21 नोएडा स्टेडियम में आज से रामलीला शुरू होगी। इसमें मुख्य अतिथि सांसद डा. महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह रहेंगे। सोमवार शाम सात बजे पहले गणेश वंदना होगी। इसके बाद नारद मोह का प्रसंग होगा। स्टेडयिम में श्री सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।

समिति के महासचिव संजय बाली ने बताया कि रामलीला के मंचन के लिए दो मंजिल का महल बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा कलाकारों ने भी अभयास शुरू कर दिया है।

पहले दिन से ही काफी भव्य मंचन होगा। सेक्टर-62 सी ब्लॉक की रामलीला सेक्टर-62 के सी ब्लॉक के रामलीला मैदान में श्री राम मित्र मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य अथिति विधायक पंकज सिंह रहेंगे। सोमवार शाम सात बजे गणेश वंदना होगी। इसके बाद रामलीला में भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कथा सुनाने का प्रसंग होगा। फिर किस तरह राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं, इसका प्रसंग होगा। समिति के महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा ने बताया कि रामलीला के सभी कलाकार सेक्टर-55 के सामुदायिक केंद्र में आ गए है और अभ्यास शुरू कर दिया है। सेक्टर-107 महर्षि आश्रम की रामलीला सेक्टर-107 महर्षि आश्रम की रामलीला मैदान में भी रामलीला मंचन की तैयारी पूरी हो चुकी है। रामलीला के पहले दिन सोमवार को गणेश वंदना और गुरु पूजा के बाद रामलीला शुरू होगी। महर्षि स्थान द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। महर्षि रामलीला समिति के वरिष्ठ प्रबंधक शिशिर श्रीवास्तव ने बताया कि विधि-विधान से पूजा अचार्ना होने के बाद रामलीला में रामजन्म का बहुत ही भव्य रूप से मंचन किया जाएगा। इसके बाद ताकड़ा वध, मारीच सुबाहु का प्रसंग किया जाएगा।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321